वर्ष 13 • अंक 5 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 21 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 2

एमजी मोटर भारत में लगाएगी दूसरा विनिर्माण संयंत्र

गौतम अदाणी ▶▶ पृष्ठ 3

अदाणी गैस को मूल कंपनी से अलग होने की मिली मंजूरी

डॉलर रु. 71.70 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 77.30 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 41575 ▲ 106 रुपये | सेंसेक्स 41170.10 ▼ 152.90 | निफ्टी 12080.90 ▼ 45.10 | निफ्टी फ्यूचर्स 12079.00 ▼ 01.90 | ब्रेंट क्रूड 58.70 डॉलर ▼ 0.40 डॉलर

एक नज़र

महाशिवरात्रि पर बंद रहेंगे शेयर और जिंस बाजार

महाशिवरात्रि पर शुक्रवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिंस वायदा बाजार और मुद्रा विनिमय बाजार में अवकाश रहेगा। इसके साथ ही सराफा और प्रमुख थोक बाजार भी बंद रहेंगे।

एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ 2 मार्च को

भारतीय स्टेट बैंक की क्रेडिट कार्ड इकाई एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट सर्विसेस का 9,000 करोड़ रुपये का आईपीओ 2 मार्च को खुलेगा और 5 मार्च को बंद होगा। एसबीआई कार्ड्स में एसबीआई की 76 फीसदी हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी कार्लाइल समूह के पाय है। एसबीआई कार्ड्स देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 18 फीसदी है।

केंद्र से मिले राज्यों को 20,000 करोड़ रुपये

केंद्र ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को को जीएसटी मुआवजे के तौर पर 19,950 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह मुआवजा अक्टूबर का है। आम तौर पर केंद्र सरकार दो महीने का मुआवजा एक साथ जारी करती है, लेकिन ऐसा पहला बार हुआ है जब केंद्र ने केवल एक महीने की रकम दी है। जीएसटी परिषद की बैठक से लगभग एक महीने पहले यह राशि 17 फरवरी को जारी की गई।

केंद्र सरकार जल्द लाएगी नई किराया नीति

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय जल्द ही नई किराया नीति लाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति से शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। पुरी ने कहा कि इस नीति के तहत मकान किराये पर देने को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जल्द ही नई किराया नीति आएगी।

नागरिकों को निकालने भारत भेजेगा तीसरी उड़ान

भारत चीन के वुहान प्रांत में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तीसरी उड़ान भेजेगा। कुछ दिनों पहले ही भारत ने वुहान से 640 भारतीयों को निकाला है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अब भी कुछ संख्या में भारतीय वुहान में फंसे हैं और उनकी गणना हो रही है। पृष्ठ 14

दूरसंचार पर सक्रिय सरकार

उद्योग व ग्राहकों के हित में क्षेत्र की सेहत सुधारने पर ध्यान देगी सरकार

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 20 फरवरी

एजीआर मामला

- **एजीआर बकाये पर राहत को लेकर दूरसंचार विभाग ने नहीं दिए कोई संकेत**
- **टाटा टेली को शेष बकाया चुकाने के लिए भेजा नया नोटिस**
- **वोडाफोन ने 1,000 करोड़ रुपये का किया भुगतान**
- **पिछले कुछ दिनों से सरकार के पास लॉबीइंग कर रहे बिड़ला और मित्तल**

वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला, भारती एयरटेल के सुनील भारती मित्तल ने पिछले कुछ दिनों में कैबिनेट मंत्रियों, शीर्ष अधिकारियों से मिलकर दूरसंचार क्षेत्र की बिगड़ती सेहत को सुधारने के लिए सहमति बनाने की खातिर खूब भागदौड़ की।

सकल समायोजित बकाये के भुगतान में राहत के लिए मित्तल और बिड़ला द्वारा केंद्र सरकार के पास लॉबीइंग के बावजूद दूरसंचार विभाग से राहत के संकेत नहीं मिले। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभाग से राहत को लेकर कुछ नहीं कहा गया है लेकिन हम दूरसंचार क्षेत्र की सेहत को दुरुस्त करने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे।

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात करने वाले मित्तल ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र पर काफी ज्यादा कर है और उसे तार्किक बनाने की जरूरत है। इस बीच सोमवार को 2,197 करोड़ रुपये बकाया चुकाने वाली टाटा टेलीसर्विसेज को पूरा बकाया अदा करने के लिए विभाग से नया नोटिस जारी किया गया है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि कंपनी पर 14,000 करोड़ रुपये का बकाया है जबकि उसने 2,197 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो केवल मूलधन है। मूलधन पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

कंपनियों द्वारा किए गए दावों की जांच के लिए सरकार ने इन कंपनियों के खातों का सत्यापन करने का निर्णय किया है। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कंपनियों का दावा वाजिब है या नहीं। जहां तक बैंक गारंटी भुनाने का सवाल है तो इस बारे में विभाग ने कानूनी राय मांगी है और उसका इंतजार कर रहा है।

अधिकारी ने कहा कि एकीकृत लाइसेंस समझौते के तहत अगर सेवा प्रदाता लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो विभाग बैंक गारंटी भुना सकता है और इसे नकदी में बदल सकता है। मंत्रालय ने इस बारे में सुझाव मांगे हैं कि 17 मार्च से पहले गारंटी भुनाई जा सकती है या नहीं। 17 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। अधिकारी ने कहा, सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि दूरसंचार कंपनियां उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें और उन्होंने भुगतान करना शुरू कर दिया है। अब तक 15,700 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। दूसरी बात यह है कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना है कि दूरसंचार उद्योग की स्थिति पर इसका कोई असर न पड़े। साथ ही सरकार का उपभोक्ताओं के प्रति भी दायित्व है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी अधिकारियों के साथ इन बैठकों में कई दूरसंचार कंपनियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें पहले ही इस बकाये का भुगतान कर देना चाहिए था। एजीआर का मुद्दा 2003 का है जब इस पर विवाद शुरू हुआ था।

सीएए का साया : टल सकता है सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

सोमेश झा
नई दिल्ली, 20 फरवरी

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों के कारण एक अहम सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण स्थगित हो सकता है। इस सर्वेक्षण का काम जनवरी में शुरू हुआ था लेकिन इसमें शामिल अधिकारियों को लगातार लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है।

लोगों को संदेह है कि इसके जरिये नागरिकता तय करने के लिए आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 78वें दौर के सर्वेक्षण को स्थगित करने का फैसला बुधवार को विशेषज्ञ समिति की बैठक में लिया गया। यह सर्वेक्षण घरेलू पर्यटन खर्च और कई संकेतकों के लिए किया जा रहा है।

एक सूत्र ने कहा कि एक विशेषज्ञ समूह की बुधवार को बैठक हुई जिसमें सर्वेक्षण के काम में लगे अधिकारियों के समक्ष देश के विभिन्न हिस्सों में पेश आ रही चुनौतियों के मद्देनजर सर्वेक्षण को टालने का सुझाव दिया गया। अब इस पर सरकार को अंतिम फैसला लेना है।

सर्वेक्षण में शामिल अधिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती यह आ रही है कि उन्हें लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्हें घर से भगा दिया जाता है या उन पर हमले किए जा रहे हैं। इससे उनके जीवन को खतरा पैदा हो गया है। लोगों को डर है कि सर्वेक्षण के काम में लगे अधिकारी जो आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल नागरिकता के निर्धारण में किया जा सकता है।

78वें दौर के सर्वेक्षण का काम इस साल जनवरी से दिसंबर के बीच किया जाना है। इसका मकसद देश में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के कई संकेतकों की मैपिंग करना है। साथ ही इससे लोगों के पलायन और मकान खरीदने की प्रवृत्ति के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। (शेष पृष्ठ 14 पर)

78वां चरण : घरेलू पर्यटन व्यय एवं विविध संकेतक सर्वेक्षण
अवधि : जनवरी-दिसंबर 2020
उद्देश्य : पर्यटन व्यय और टिकाऊ विकास लक्ष्य, 2030 के लिए विकास संकेतकों के बारे में जानकारी एकत्र करना
दायरे में शामिल विषय : खाद्य असुरक्षा, परिवारों में सुविधाएं, शिक्षा, कौशल, प्रवास, आवासीय संपत्तियों की खरीद या निर्माण, जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल/इंटरनेट का इस्तेमाल
स्थिति : सीएए और एनआरसी को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए विशेषज्ञ समिति ने सर्वेक्षण को टालने की सिफारिश की है

कारोबारी सुगमता सुधारने की कवायद

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 20 फरवरी

- **दिल्ली के उप राज्यपाल ने कारोबारी सुगमता पर की समीक्षा बैठक**
- **प्रदूषण घटाने के लिए 27 फरवरी को पर्यावरण सम्मेलन**

राज्यों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में दिल्ली की स्थिति काफी खराब है। ऐसे में दिल्ली में कारोबारी सुगमता सुधारने की कवायद चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में उप राज्यपाल अनिल बैजल ने आज कारोबारी सुगमता पर समीक्षा बैठक की। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने कारोबारी सुगमता पर समीक्षा बैठक के बाद कहा, 'हमें यूटिलिटी कनेक्शन के डिजिटलीकरण, स्वत: नामांतरण के साथ संपत्ति का ऑनलाइन पंजीयन, सभी संपत्तियों के लिए यूनिक आईडी, शिकायतों की ई-फाइलिंग की व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे कि दिल्ली में कारोबारी सुगमता का माहौल मुहैया हो सके।' राज्यों की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में दिल्ली 23 वे स्थान पर है।

इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल ने प्रदूषण में कमी पर अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली में प्रदूषण में कमी लाने के लिए 27 फरवरी को पर्यावरण सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों और अधिकारियों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाएगी। सरकार पड़ोसी राज्यों से भी प्रदूषण में कमी के लिए मदद लेगी और अगले माह पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक करेगी। दिल्ली में प्रदूषण के मामले में ज्यादा प्रदूषित माने जाने वाले स्थानों में वर्ष 2019 में इससे पहले वाले वर्ष के मुकाबले प्रदूषण मानक स्तर पीएम-10 और पीएम-2.5 में कमी दर्ज की गई है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लीनिक के संचालन की समीक्षा कर विभाग को नए मोहल्ला क्लीनिक खोलने से संबंधित कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जांच केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए।

विभाग भेज रहा 2 रु. वसूली के कर नोटिस

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 20 फरवरी

- **ब्याज मद में बकाये मद से कर विभाग को मिल सकते हैं 46,000 करोड़ रुपये**

- **जीएसटी रिटर्न में देरी पर ब्याज देनदारी को लेकर भेजे जा रहे हैं नोटिस**
- **कई सारे कारोबारियों को 2 से 5 रुपये तक के मिले हैं कर नोटिस**

कर विभाग की ओर से 2 रुपये का भुगतान करने का नोटिस भेजा जाना आपको भले ही अजीब लग सकता है लेकिन हाल के दिनों में कई कारोबारियों को इस तरह के नोटिस मिले हैं। असल में, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न देरी से भरने को लेकर ब्याज भुगतान के लिए कंपनी को इस तरह की छोटी राशि के लिए भी नोटिस भेजे जा रहे हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी ब्याज मद में बकाया 46,000 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर निर्देश मिलने के बाद क्षेत्रीय अधिकारी इन दिनों वसूली का नोटिस भेजने में व्यस्त हैं और कुछ मामलों में तो 10 रुपये से भी कम का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजे गए हैं।

इक्विटी इन्फॉर्मेशन सेवा से जुड़े एक ग्राहक को 5 रुपये की ब्याज राशि जमा कराने को कहा गया है, वहीं एक अन्य से 2 रुपये का बकाया मांगा गया है। एक कंपनी को तो शून्य रुपये का नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उन पर पूर्ण अंक में इतनी ही देनदारी बन रही थी। वित्त वर्ष 2020 में जीएसटी संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग ब्याज मद में बकाया राशि को वसूलने में सख्ती दिखा रहा है।

अप्रैल से जनवरी के दौरान केंद्रीय जीएसटी संग्रह 10.4 फीसदी बढ़ा है जबकि पूरे वित्त वर्ष के संशोधित लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाकी बचे दो महीने में कर संग्रह 21 फीसदी बढ़नी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी मामूली राशि के लिए नोटिस जारी करना कारोबारी सुगमता के बजाय कर आतंकवाद को बढ़ावा देने की तरह है। तय समय पर रिटर्न नहीं भरने पर केंद्रीय जीएसटी के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये और राज्य जीएसटी के लिए भी इतनी ही राशि का विलंब शुल्क वसूला जाता है। इसके साथ ही इस पर 18 फीसदी का ब्याज भी वसूला जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया है करदाता अपनी देनदारी के एक हिस्से का नकद भुगतान कर सकते हैं शेष इनपुट टैक्स क्रेडिट में समायोजित करा सकते हैं।

एएमआरजी एसोसिएट के पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि मामूली रकम के लिए कर नोटिस जारी करने से कर आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, वहीं कारोबारियों के बीच नकारात्मक धारणा बनेगी।

सीबीआईसी ने 10 फरवरी को लिखे पत्र में क्षेत्रीय अधिकारियों से कहा है कि वह ब्याज देनदारी नहीं चुकाने वालों से उसकी वसूली की प्रक्रिया शुरू करें।

हालांकि इसमें स्पष्टता नहीं है कि ब्याज सकल कर देनदारी पर वसूली जाएगी या शुद्ध नकद देनदारी पर। डेलॉयट इंडिया के एमएस मणि ने कहा कि अगर कर अधिकारी द्वारा केवल शुद्ध देनदारी पर ब्याज वसूली के स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं तो कारोबारी इसका स्वागत करेंगे।

खबरों में रहे स्टॉक

मैक्स फाइनैंशियल सर्विसेज

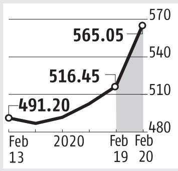

मैक्स लाइफ संग दीर्घावधि रणीतिक साझेदारी कर सकता है ऐक्सिस बैंक

₹ 516.45 पिछला बंद भाव
₹ 565.05 आज का बंद भाव
▲ 9.39 %

मुथूट फाइनैंस

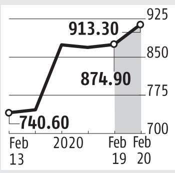

बाजार पूंजीकरण में आईडीबीआई बैंक, पीएनबी को पछाड़ा

₹ 876.90 पिछला बंद भाव
₹ 913.30 आज का बंद भाव
▲ 4.39 %

भारतीय स्टेट बैंक

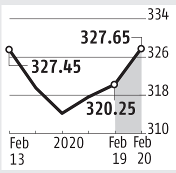

एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ 2 मार्च का खुलकर 5 मार्च को बंद होगा

₹ 320.25 पिछला बंद भाव
₹ 327.65 आज का बंद भाव
▲ 2.31 %

एस्कॉर्ट्स

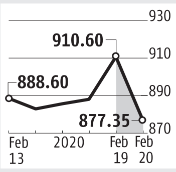

प्रवर्तन निदेशालय अभी नहीं कर रहा कोई जांच

₹ 910.60 पिछला बंद भाव
₹ 877.35 आज का बंद भाव
▼ 3.65 %

शोभा

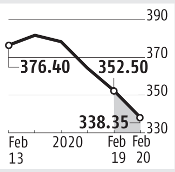

फरवरी में अब तक 25 फीसदी लुढ़का शेयर

₹ 352.50 पिछला बंद भाव
₹ 338.35 आज का बंद भाव
▼ 4.01 %

संक्षेप में

एसी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाएगी पैनासोनिक

पैनासोनिक इंडिया अगले वित्त वर्ष तक घरेलू एयर कंडीशनर (एसी) बाजार में 10 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पिछले साल कंपनी की हिस्सेदारी 6 फीसदी थी। इसी क्रम में कंपनी ने अपने इंटरनेट से जुड़े एसी (कनेक्टेड एसी) की नई श्रृंखला भी पेश की। *भाषा*

भूल सुधार

गुरुवार 20 फरवरी के अंक में प्रकाशित समाचार 'टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन होंगे सस्ते' में कंपनी ने कीमतों को युक्तिसंगत बनाने की बात कही थी, जहां कंपनी का आशय कीमत बढ़ाने से था। किंतु असावधानीवश वाहनों के दाम घटाने की बात प्रकाशित हो गई। त्रुटि के लिए खेद है।

वाहनों की खुदरा बिक्री में गिरावट लगातार जारी

डीलरों ने कहा, रुझान नहीं सुधरने से ग्राहक अब भी टाल रहे खरीदारी

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 20 फरवरी

वाहनों की बिक्री लगातार घट रही है। वाहन डीलरों का कहना है कि खरीदारों का भरोसा अभी लौटा नहीं है, जिनमें से बहुत से लोग कार खरीदने के अपने फैसले को टाल रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सुधार नजर आ रहा है, जहां ट्रैक्टरों की बिक्री में बढ़ोतरी नजर आ रही है।

वाहन डीलरों की शीर्ष संस्था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में वाहनों की खुदरा बिक्री जनवरी 2019 के मुकाबले 7.17 फीसदी गिरकर 2,90,879 रही। आम तौर पर दिसंबर में अच्छी बिक्री के बाद जनवरी में खुदरा बिक्री कमजोर रहती है, लेकिन कमजोर उपभोक्ता रुझान और अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी से इस साल मांग में गिरावट बढ़ी है। फाडा के अध्यक्ष आशीष काले ने कहा, 'तिपहिया को छोड़कर वाहनों की बिक्री जनवरी में घटी है। बहुत से ग्राहक अभी अपने फैसले टाल रहे हैं।' फाडा के आंकड़ों के मुताबिक कुल वाहनों में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखने वाले खंड यात्री वाहन की खुदरा बिक्री अक्टूबर में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 4.61 फीसदी गिरकर 2,90,879 रही है।

जनवरी लगातार दूसरा ऐसा महीना है, जब यात्री वाहनों की शोरूम बिक्री में गिरावट आई है। इससे पहले अक्टूबर और नवंबर में यात्री वाहनों की बिक्री में मामूली सुधार रहा था। उस समय वाहन कंपनियों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए भारी-भरकम छूट दी थीं।

हालांकि आर्थिक गतिविधियों में नरमी और ट्रकों की माल ढोने की क्षमता में बढ़ोतरी के कारण ट्रांसपोर्टरों के पास जरूरत से अधिक क्षमता हो जाने से भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री जनवरी में 6.89 फीसदी लुढ़ककर 82,187 पर आ गई।

ज्यादातर वाहन कंपनियों ने पिछले महीने थोक बिक्री में गिरावट दर्ज की है क्योंकि बीएस-4 वाहनों का स्टॉक नियंत्रित रखने के लिए उत्पादन घटाया गया और डीलरों को बीएस6 वाहन ज्यादा भेजना शुरू किया गया है। नए उत्सर्जन नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएंगे।

काले ने कहा जनवरी में तिपहिया को छोड़कर ज्यादातर वाहनों की बिक्री में गिरावट रही। उन्होंने कहा कि बीएस-6 उत्सर्जन नियमों को लागू करने से भी खरीदारी टाली जा रही है। काले ने कहा, 'कमजोर मांग के कारण डीलर बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर सबसे अधिक जोर दे रहे हैं। फाडा पहले ही सभी विनिर्माताओं से बीएस-6 को अपनाने की अपील कर चुका है।

वाहन बिक्री के आंकड़े

श्रेणी	जन. 2020	जन. 2019	वृद्धि (%)
दोपहिया	12,67,366	13,89,951	-8.82
तिपहिया	63,514	58,178	9.17
वाणिज्यिक वाहन	82,817	88,271	-6.18
यात्री वाहन	2,90,879	3,04,929	-4.61
ट्रैक्टर	46,170	43,924	5.11
कुल	17,50,746	18,85,253	-7.13

स्रोत : फाडा

एमजी मोटर बढ़ाएगी क्षमता

कंपनी भारत में अपना दूसरा संयंत्र लगाने की कर रही तैयारी

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 20 फरवरी

देश में अपनी कारों की बढ़ती मांग और भविष्य के मॉडलों के विनिर्माण को देखते हुए एमजी मोटर अपने उत्पादन में सुधार लाने की योजना बना रही है। इसी क्रम में कंपनी भारत में अपना दूसरा संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाश रही है। भविष्य के मॉडलों में भारतीय बाजार के लिए एक सस्ती एक इलेक्ट्रिक कार भी शामिल हो सकती है।

कंपनी अपना फुल-साइज एसयूवी एमजी ग्लोस्टर को उतारने की योजना बना रही है जिसके लिए कीमत दायरा 40 से 50 लाख रुपये होगा। इस साल दीवाली तक इस मॉडल के बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। भारतीय बाजार में डेढ़ वर्ष के परिचालन के दौरान कंपनी के चार मॉडल उपलब्ध होंगे। कंपनी एक अन्य एसयूवी लाने की योजना बना रही है जो उसके पांचवें मॉडल के तौर पर 2021 में बाजार में दस्तक देगा। बाजार में उसकी आपूर्ति के लिए कंपनी को एक नए विनिर्माण संयंत्र की आवश्यकता होगी।

गुजरात के हलोल में एमजी मोटर के विनिर्माण संयंत्र की क्षमता 80 हजार से 1 लाख वाहनों के उत्पादन की है। पहले यह संयंत्र का स्वामित्व जनरल मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास था। एमजी मोटर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी गौरव गुप्ता ने कहा कि कंपनी ने उत्पादन क्षमता को 3,000 से बढ़ाकर 3,500 वाहन कर दिया और अब उसे बढ़ाकर 4,000 वाहन करने की योजना है। भारतीय बाजार में कंपनी द्वारा उतारे गए पहले वाहन हेक्टर के लिए प्रतीक्षा अवधि पहले छह महीने थी जो घटकर अब 3 से 4 महीने रह गई है। उत्पादन क्षमता में विस्तार किए जाने पर प्रतीक्षा अवधि में और गिरावट आएगी।

गुप्ता ने कोरोनावायरस के प्रभाव के बारे में कहा कि फरवरी में उत्पादन प्रभावित हो रहा है और फिलहाल कंपनी अपनी योजना के मुताबिक उत्पादन बढ़ाने में समर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आपूर्तिकर्ताओं के संयंत्र बंद रहे तो मार्च में भी हमारा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उत्पादन में कितनी गिरावट आएगी।

भारत में एमजी मोटर के पहले मॉडल हेक्टर की बिक्री 50,000 वाहनों के पार हो चुकी है। कंपनी ने दावा किया है कि यह भारत की पहली इंटरनेट कार है और यह सी-एसयूवी श्रेणी में बाजार की अग्रणी कार बनकर उभरी है। पिछले साल भारतीय बाजार में उतारे जाने के बाद इसकी अब तक करीब 20,000 वाहनों की बिक्री हो चुकी है।

गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित दूसरा संयंत्र दक्षिण भारत में हो सकता है। उन्होंने कहा कि उसकी क्षमता मौजूदा संयंत्र के मुकाबले अधिक होगी क्योंकि कंपनी नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों का भी उत्पादन कर सकती है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि नए संयंत्र पर कितना निवेश किया जाएगा। एमजी मोटर ने हलोल संयंत्र में करीब 5,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताई थी और अब तक वह करीब 2,000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है। शेष रकम का निवेश आगामी महीनों में किया जाएगा।

क्षमता विस्तार

- कंपनी अपने वाहनों की बढ़ती मांग और भविष्य के मॉडलों के उत्पादन के लिए नए विनिर्माण संयंत्र लगाएगी
- गुजरात के हलोल में एमजी मोटर के विनिर्माण संयंत्र की क्षमता 80 हजार से 1 लाख वाहनों के उत्पादन की है

बीमा कवर बढ़ाने से निर्यातकों की लागत घटेगी: एसबीआई

भाषा
मुंबई, 20 फरवरी

निर्यातकों से वसूली में आ रही कठिनाइयों का जिक्र करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रमुख रजनीश कुमार ने गुरुवार को निर्यात वित्तपोषण के तरीकों में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि बीमा कवर को 90 फीसदी तक बढ़ाकर निर्यातकों की लागत में कमी और उनके कारोबार में तेजी लाई जा सकती है।

कुमार ने प्रमुख निर्यात संस्था फियो द्वारा आयोजित एक बैंकिंग सम्मेलन में कहा, निर्यातकों के बिल या देनदारियों की विधि को बदलना होगा। जब इसमें सहयोगी या सहायक इकाईयां शामिल होती हैं, जहां सहयोगियों या सहायक कंपनियों के माध्यम से कारोबार किया जाता है, ऐसे मामलों में हमारा अनुभव बेहद खराब रहा है,। उन्होंने कहा कि कि निर्यातकों को धन देते समय बंधक या गिरवी से बैंकों को कुछ राहत मिलती है, लेकिन वसूली के मामले में ए बहुत मददगार नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, कई विवाद हैं और बंधक से वसूली करने में लंबा समय लगता है।

प्रस्ताव के खिलाफ बढ़ रहा एमएफ का मतदान

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 20 फरवरी

म्युचुअल फंड अभी भी भारतीय कंपनी जगत के साथ सीधा संघर्ष करने में हिचकते हैं लेकिन शेयरधारक प्रस्तावों के खिलाफ उनके मतदान में पिछले कैलेंडर वर्ष के मुकाबले तेजी आई है।

वर्ष 2019 में खिलाफ मतों का प्रतिशत बढ़कर 4.23 फीसदी हो गया जो पिछले पांच वर्षों का सर्वाधिक आंकड़ा है। वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 3.4 फीसदी रहा था। विकसित बाजारों में संस्थागत निवेशकों ने आमतौर पर कंपनियों द्वारा लाए गए 5 से 10 फीसदी शेयरधारक प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया। हालांकि शीर्ष 10 फंड हाउस के महज 3.3 फीसदी वोट प्रबंधन के खिलाफ गए।

प्राइमएमएफडेटाबेस के आंकड़ों से पता चलता है कि इनमें से छह फंड हाउसों- आदित्य बिड़ला सन लाइफ, एचडीएफसी एमएफ, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एमएफ, कोटक एमएफ, आईडीएफसी एमएफ और ऐक्सिस एमएफ- ने इस तरीके से 0.1 फीसदी से भी कम मतदान किया। जबकि अनुपस्थित रहने वाले मतों का प्रतिशत घटकर 10.9 फीसदी रह गया जो एक साल पहले 12.5 फीसदी रहा था। जबकि 2010 के दशक के शुरुआती वर्षों में यह आंकड़ा 80 से 90 फीसदी के दायरे में रहा था। इस लिहाज से इसमें जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई।

वैल्यू रिसर्च के मुख्य कार्याधिकारी धीरेंद्र कुमार ने कहा, 'पहले आधे से अधिक उद्योग मतदान नहीं करता था। यही कारण है कि अनुपस्थित रहने वाले मतों की संख्या घटकर 11 फीसदी रह गई और प्रस्ताव के खिलाफ मतदान में मामूली तेजी आई है। इसे सकारात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए।' आम बैठक में मतदान अल्पांश शेयरधारक के लिए कंपनी के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने का हथियार है।

आईआईएएस के संस्थापक अमित टंडन ने कहा, 'महज निशान लगा देने के नजरिये के बजाय अब मतदान के बारे में कहीं अधिक सोच-विचार किया जाने लगा है। फंड हाउस संबंधित कंपनी के निर्णय में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।' भारतीय म्युचुअल फंडों कर मतदान करने का तरीका उल्लेखनीय है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान उन्हें काफी उतार-चढ़ाव से जूझना पड़ा है। 7.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक की इक्विटी पूंजी के साथ म्युचुअल फंड बाजार का रुख तेजी से बदल रहे हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान म्युचुअल फंडों का शुद्ध निवेश 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के कुल 67,098 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 2.5 गुना अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह केवल प्रतिशत ही नहीं है बल्कि प्रस्ताव के खिलाफ मतों का प्रकार मायने रखता है। इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक श्रीराम सुब्रमण्यन ने कहा, 'भारतीय संस्थागत निवेशकों को महत्त्वपूर्ण कंपनी मामलों जैसे निदेशकों एवं ऑडिटरों की नियुक्ति आदि में दखल देनी चाहिए। उसे खुद को शेयर जारी करने अथवा बढ़ते ऋण जैसे पूंजीगत ढांचे में बदलाव से संबंधित मामलों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए।'

म्युचुअल फंड कई कंपनियों के लिए लिक्विड परिसंपत्तियों का प्रबंधन करते हैं।

अदाणी गैस को मिली मूल कंपनी से अलग होने की इजाजत

एजेंसियां
नई दिल्ली, 20 फरवरी

अदाणी गैस को तेल एवं गैस क्षेत्र के नियामक से अपनी मूल कंपनी से अलग होने के साथ-साथ फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटाल को हिस्सेदारी बेचने की अनुमति मिल गई है। सूत्रों ने जानकारी दी कि कंपनी के आधिकारिक तौर पर अनुमति मांगे जाने के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले पीएनजीआरबी ने अदाणी गैस को 13 शहरों में गैस वितरण के लिए मिला लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसकी वजह कंपनी का मूल कंपनी से अलग होने की जानकारी साझा ना करके कथित तौर पर धोखाधड़ी करना था। कंपनी को यह लाइसेंस 2018 में नौंवे दौर की बोली के दौरान मिला था।

पीएनजीआरबी के 29 नवंबर 2019 को अदाणी गैस को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर कंपनी ने कहा कि उसने इस संबंध में सभी संबंधित प्राधिकारों को मीडिया, अखबार, सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक सूचीबद्धता और बोली दस्तावेजों के माध्यम से अदाणी गैस लिमिटेड के पुनर्गठित किए जाने की जानकारी दी है। लेकिन पीएनजीआरबी ने इस संबंध में कंपनी मामलों के मंत्रालय से धोखाधड़ी को लेकर जांच कराने की चेतावनी दी और कंपनी पर 396.81 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद कंपनी का 13 शहरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद कंपनी ने हिस्सेदारी बेचने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया और इस पर पीएनजीआरबी ने अनुमति दे दी।

पीएनजीआरबी ने हालांकि कंपनी से कहा कि उसे हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी समय पर मांगनी चाहिए थी। कंपनी के प्रवक्ता इस बारे में टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए।

मूल रूप से अदाणी गैस, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) का हिस्सा थी और अदाणी फैमिली की 74.8 फीसदी हिस्सेदारी का आधा टोटाल को बेचने से पहले उसे अलग इकाई बनाया गया।

पीएनजीआरबी ने नवंबर के नोटिस में कहा था कि सिटी गैस वितरण के लिए बोली लगाने के समय वह एकीकरण और कारोबार अगल करने की योजना लागू कर रही थी और इससे वाकिफ थी कि इसके परिणामस्वरूप एईएल से एजीएल के प्रवर्तक में बदलाव होगा। एजीएल ने बोली के मानकों पर खरा उतरने के लिए एईएल की हैसियत का इस्तेमाल किया और स्वामित्व में बदलाव के बारे में खुलासा न करना धोखाधड़ी था।

अक्टूबर 2018 में अदाणी समूह ने ऑटोमोबाइल व पाइप्ड रसोई गैस घरों तक पहुंचाने के लिए सीएनजी की खुदरा बिक्री खातिर टोटाल के साथ 50-50 फीसदी हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम बनाने पर सहमति दी थी। एक साल बाद टोटाल ने अदाणी गैस की 37.4 फीसदी हिस्सेदारी करीब 5,700 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए करार किया। पिछले महीने जब पीएनजीआरबी के नोटिस की खबर आई तो अदाणी गैस ने कहा था कि उसने पीएनजीआरबी को सभी आवश्यक सूचनाएं दी है। अदाणी गैस के प्रवक्ता ने कहा था कि हमने कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों का पालन किया है। उल्लेखनीय है कि हम पूरी तरह अनुपालन करने वाले हैं और पारदर्शी तरीके से तथ्यों की सूचना दी, जो अनुपालन व खुलासा नियमों के मुताबिक था।

कारोबार अलग करने की अनुमति

- कंपनी के आधिकारिक तौर पर अनुमति मांगे जाने के बाद पीएनजीआरबी ने मंजूरी दे दी है
- इससे पहले पीएनजीआरबी ने अदाणी गैस को 13 शहरों में गैस वितरण के लिए मिला लाइसेंस रद्द कर दिया था और जुर्माना भी लगाया था

म्युचुअल फंड कारोबार में उतरने का जीरोधा का इरादा

छूट वाले ब्रोकर जीरोधा की योजना पैसिव फंडों के इर्द-गिर्द कारोबारी मॉडल बनाने की है

जश कृपलानी
मुंबई, 20 फरवरी

देश की सबसे बड़ी ब्रोकिंग कंपनी जीरोधा 27 लाख करोड़ रुपये वाले म्युचुअल फंड उद्योग में उतरने पर विचार कर रही है और फर्म ने बाजार नियामक से सेबी के पास म्युचुअल फंड लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। जीरोधा के संस्थापक व मुख्य कार्याधिकारी नितिन कामत ने कहा, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो अलग-अलग योजनाओं की पेशकश कर सके। पैसिव फंडों में हम नवोन्मेषी योजनाएं लाना चाहते हैं, जो निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

जीरोधा पहले से ही म्युचुअल फंड वितरण प्लेटफॉर्म कॉइन का परिचालन कर रही है, जो ग्राहकों को डायरेक्ट प्लान की पेशकश करता है। कामत ने कहा कि कॉइन के परिचालन से उनकी टीम को निवेशकों का व्यवहार और निवेशकों के लिए उपयुक्त योजनाओं के बारे में समझने में मदद मिली है।

हाल के महीनों में पैसिव फंड निवेशकों के बीच लोकप्रिय हुआ है और सक्रियता से प्रबंधित फंड बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन में चुनौतियों का सामना कर रहा है।

साल 2019 में सक्रियता से प्रबंधित इक्विटी योजनाओं के आधे ने अपने बेंचमार्कों के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया है। इंडेक्स फंडों की तरफ से प्रबंधित कुल परिसंपत्तियों में भी मौजूदा वित्त वर्ष में बढ़ोतरी नजर आई है। वित्त वर्ष की शुरुआत की 5,286 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के मुकाबले जनवरी 2020 में यह करीब 50 फीसदी बढ़कर करीब 8,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि सेबी के कदम से अलग-अलग योजनाओं का बास्केट बनाने के लिए और फिनटेक कंपनियां आकर्षित हो सकती हैं। कामत ने कहा, हमें यह देखना होगा कि यह ढांचा कैसे काम करेगा। जीरोधा ने एमएफ लाइसेंस के लिए 5 फरवरी 2020 को आवेदन किया। जिन कंपनियों के आवेदन सेबी के पास हैं उनमें श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस और फ्रंटलाइन कैपिटल सर्विसेज शामिल है।

हाल में सेबी ने ब्रोकिंग कंपनी सैमको सिक्योरिटीज और एनजे इंडिया के एमएफ लाइसेंस को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कमीशन के लिहाज से एनजे इंडिया देश की सबसे बड़ी म्युचुअल फंड वितरक है।

संक्षेप में

प्रवर्तक, आईएफसी से रकम जुटाएगी फ्यूचर

किशोर बियाणी की अगुआई वाली फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन ने गुरुवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल ने अपने प्रवर्तकों व इंटरनैशनल फाइनैंस कॉरपोरेशन से 600 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी है। कर्ज घटाने और सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रकम जुटाई जाएगी। निदेशक मंडल ने एनसीडी से 400 करोड़ रुपये जुटाने की भी मंजूरी दी है। *बीएस*

सिंगापुर की कंपनी करेगी 1.5 अरब डॉलर निवेश

एलएनजी व गैस लॉजिस्टिक्स व वितरण समाधान वाली वैश्विक दिग्गज सिंगापुर की अटलांटिक गल्फ ऐंड पैसिफिक ने कहा है कि वह दक्षिण भारत में करीब 1.5 अरब डॉलर निवेश करेगी। कंपनी ने पुडुचेरी के कराइकल बंदरगाह में एलएनजी आयात सुविधा का शिलान्यास किया। यह सुविधा 2021 की चौथी तिमाही से वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर सकती है। *बीएस*

फिच की नकारात्मक सूची से भारती एयरटेल बाहर

फिच रेटिंग्स ने भारती एयरटेल को नकारात्मक निगरानी सूची से हटा दिया और स्थिर परिदृश्य के साथ उसकी बीबीबी- रेटिंग बरकरार रखी है। *भाषा*

फिनटेक फर्मों व यूपीआई को प्रतिस्पर्धी मान रही एसबीआई काड्‌र्स

अनूप रॉय
मुंबई, 20 फरवरी

एसबीआई काड्‌र्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज नई पीढ़ी फिनटेक की अगुआई वाले भुगतान समाधान को बड़ी प्रतिस्पर्धी मान रही है। कंनपी ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के मसौदा दस्तावेज में ये बातें कही है। आईपीओ में जाने से पहले किसी कंपनी के लिए जोखिम वाले कारकों को सामने रखना अनिवार्य होता है ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी हो।

अपनी विवरणिका में एसबीआई काड्‌र्स ने कहा है कि कंपनी के लिए प्राथमिक प्रतिस्पर्धा अन्य क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों से बनी रहेगी और यहां तक कि कुछ हद तक डेबिट कार्ड जारी करने वालों से भी।

हालांकि नवोन्मेषी योजनाओं के साथ नई कंपनियां भी उभरी हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी को उन कारोबारों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है जो खुद के मोबाइल वॉलेट का संचालन कर रहे हैं या अपने ग्राहकों को उधार दे रहे हैं। साथ ही अन्य फिनटेक सेवा प्रदाता भी उनकी प्रतिस्पर्धी हैं। एसबीआई काड्‌र्स ने अपनी विवरणिका में कहा है, खास तौर से मोबाइल, ई-वॉलेट और टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म (यूपीआई समेत) से कड़ा मुकाबला हो सकता है क्योंकि ये मर्चेंट को काफी कम या कोई प्रसंस्करण शुल्क न देकर काफी कारोबार अपनी ओर खींच सकते हैं।

मैक्स लाइफ में हिस्सेदारी लेगा ऐक्सिस बैंक!

निजी क्षेत्र के ऐक्सिस बैंक ने मैक्स फाइनैंशियल सर्विसेज और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक विशेष समझौता किया है ताकि जीवन बीमा इकाई में दीर्घावधि रणनीतिक साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जा सके। इसके तहत ऐक्सिस बैंक इस जीवन बीमा कंपनी में उल्लेखनीय हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर सकता है। मैक्स फाइेंशियल सर्विसेज और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड की आज हुई बैठक में ऐक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की संभावनाएं तलाशने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसमें ऐक्सिस बैंक द्वारा कंपनी में उल्लेखनीय हिस्सेदारी के अधिग्रहण की भी बात कही गई है। *बीएस*

डीएचएफएल का कर पूर्व घाटा 167.80 करोड़ रुपये

सुब्रत पांडा
मुंबई, 20 फरवरी

संकट में फंसी दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड का कर पूर्व नुकसान दिसंबर तिमाही में 167.80 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की समान अवधि में कंपनी ने 471.5 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया था। सितंबर तिमाही में कंपनी ने 7,584.43 करोड़ रुपये का कर पूर्व नुकसान दर्ज किया था।

हालांकि कंपनी का शुद्ध लाभ दिसंबर 2019 की तिमाही में 934.35 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 313.6 करोड़ रुपये रहा था। इसकी वजह वित्त वर्ष 2019 के पहले नौ महीने में 1,973 करोड़ रुपये का कर समायोजन रही।

कंपनी ने हालांकि कहा कि दिवालिया की तारीख की घोषणा के बाद से उधारी पर 527.62 करोड़ रुपये के ब्याज के लिए उसने प्रावधान नहीं किया है, जो कानूनी सलाहकार की राय पर आधारित है। कंपनी ने कहा, दिवालिया संहिता के तहत समाधान योजना के तहत लेनदारों के साथ व्यवहार दिवालिया की घोषणा की तारीख तक के कर्ज पर होता है और उसके बाद न तो कोई ब्याज अर्जित होता है और न ही इस तारीख के बाद उसका भुगतान होता है। अगर उधारी पर ब्याज अर्जित हुआ होता तो तिमाही और नौ महीने की अवधि के लिए लाभ 392.39 करोड़ रुपये कम होता।

लेनदार की ब्याज आय तिमाही में 28 फीसदी घटकर 2,384.12 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 3,314.49 करोड़ रुपये रही थी।

नीतिगत दरों में कटौती के लिए मौद्रिक नीति समिति को उचित समय का इंतजार

बीएस संवाददाता
मुंबई, 20 फरवरी

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्यों ने बैंकों को पिछली कटौतियों का लाभ ग्राहकों को देने और भविष्य में दरों में कटौती के असर को अधिकतम करने के लिए इंतजार करने का फैसला किया है। साथ ही समिति सरकार की ओर से वृद्धि दर बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का अर्थव्यवस्था पर असर भी देखना चाहती है।

पहले की नीतियों के विपरीत समिति के 6 सदस्य महंगाई दर को लेकर बहुत चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें भरोसा था कि महंगाई में कमी आएगी। सदस्यों ने कोरोनावायरस के संकट और उसके आर्थिक जोखिम पर भी चर्चा की।

दिसंबर महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर 7.35 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो रिजर्व बैंक के 6 प्रतिशत के अनुमान से बहुत ज्यादा है। महंगाई दर खासकर प्याज के दाम में तेजी की वजह से बढ़ी है। सदस्यों ने पाया कि प्याज के दाम 328 प्रतिशत बढ़े, जिसने 0.64 प्रतिशत का छोटा अधिभार होने के बावजूद अकेले महंगाई दर में 210 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई। रिजर्व बैंक के सर्वे के मुताबिक 3 महीने बाद महंगाई दर 60 आधार अंक और एक साल में 70 आधार अंक सुधरने की उम्मीद है।

सदस्यों ने यह भी पाया कि सरकार द्वारा वृद्धि के समर्थन में उठाए गए कदम और कर में कटौती से अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, लेकिन कम अवधि में इसका तत्काल असर नहीं पड़ेगा।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कुछ बेहतर परिणाम दिख रहे हैं। दास ने कहा, 'मौद्रिक नीति नीचे तक पहुंचाए जाने और बैंक के कर्ज के प्रवाह में सुधार है, लेकिन उन्हें मजबूत होने की जरूरत है। व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए अभी आगे और मौद्रिक प्रोत्साहन की जरूरत है, वहीं महंगाई का परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है।'

रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक और हाल में शामिल सदस्य जनक राज ने कहा कि हाल में महंगाई में आई तेजी से गांवों की आमदनी में सुधार होगा और इससे ग्रामीण मांग बढ़ेगी। कोरोनावायरस के संकट पर राज ने कहा, 'इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर होगा और अगर तेल व अन्य वैश्विक जिंसों के दाम में गिरावट आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका शुद्ध असर नकारात्मक हो सकता है।'

डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र ने कहा कि इस बात के कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं कि अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर पहुंचकर ऊपर की ओर आ रही है। पात्र ने कहा, 'फरवरी 2019 से नीतिगत दरों में अब तक की गई 135 आधार अंकों की कमी के प्रयासों का असर अब नजर आएगा और इस पर न्यायपूर्ण व प्रभावी तरीके से काम करने पर अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा।'

समिति के सदस्यों की राय

- समिति के **6** सदस्य महंगाई दर को लेकर नहीं दिखे बहुत चिंतित
- सितंबर **2019** में कॉर्पोरेट कर में कटौती का कंपनियों के मुनाफे पर नहीं दिखा असर
- अगर नीतिगत दरों में **135** आधार अंक की कटौती और जीडीपी के **1.2** प्रतिशत के बराबर प्रोत्साहन पैकेज का असर नहीं हो तो और ढांचागत सुधार की जरूरत
- सुधार के थोड़े संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियां कमजोर

बाहरी सदस्य चेतन घाटे ने के मुताबिक सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट कर में कटौती का तीसरी तिमाही में कंपनियों के शुद्ध मुनाफे पर कोई असर नहीं पड़ा है, जो रिजर्व बैंक के औद्योगिक परिदृश्य सर्वे (आईओएस) से पता चलता है। चौथी तिमाही में भी मुनाफे की स्थिति निराशाजनक बने रहने की उम्मीद है।

घाटे ने कहा, 'अगर नीतिगत दरों में 135 अंक की कटौती और जीडीपी के 1.2 प्रतिशत राशि के बराबर प्रोत्साहन पैकेज देने के बावजूद वृद्धि बहाल नहीं होती है तो और ज्यादा ढांचागत सुधार करना वक्त की जरूरत है।'

एक और बाहरी सदस्य पमी दुआ ने कहा कि मामूली सुधार के जहां थोड़े संकेत मिल रहे हैं, कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं।

बाहरी सदस्य रवींद्र ढोलकिया ने उचित समय पर दरों में कटौती के लिए जगह बनाए रखने की वकालत की। उन्होंने कहा, 'हमें राज्यों के बजट के बाद तक राजकोषीय नीति के लिए इंतजार करने की जरूरत है।' ढोलकिया ने कहा, 'अगर दीर्घावधि के हिसाब से बहाली की गंभीर कवायद नहीं की जाती है तो कम अवधि के हिसाब से रिकवरी के लिए की गई कवायद भी नाकाफी हो सकती है। मौद्रिक नीति प्रोत्साहन अप्रत्यक्ष होती है और बगैर किसी सहारे के यह कम प्रभावी हो सकती है।'

बिजली क्षेत्र को नई योजना से आस

देव चटर्जी
मुंबई, 20 फरवरी

भारतीय ऋणदाताओं के संकटग्रस्त बिजली क्षेत्र में करीब 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज फंसा पड़ा है। ऐसे में ऋणदाता अब सरकार की नई योजना की ओर देख रहे हैं जिससे मानक ताप बिजली परियोजनाओं को बचाया जा सकता है और बैंक को अपनी फंसी पूंजी की वसूली में मदद मिल सकती है।

बिजली मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की एनटीपीसी, बिजली वितरण कंपनियों और बैंकरों सहित सभी हितधारकों के साथ नई दिल्ली में शुक्रवार को बैठक प्रस्तावित है। बैठक में मंत्रालय की प्रस्तावित योजना पर विचार किया जाएगा।

एक बैंकर ने कहा, 'अक्षय ऊर्जा को तापीय बिजली परियोजनाओं के साथ जोड़ने के विकल्प पर चर्चा की गई है जिससे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी, वहीं तापीय बिजली संयंत्रों को बचाया जा सकेगा और कर्ज की वसूली भी संभव हो सकेगी।'

उन्होंने कहा, 'दोनों को जोड़ने से उपभोक्ता, बिजली उत्पादक, वितरक, पारेषण कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों को मदद मिलेगी।' अगर योजना परवान चढ़ती है तो इससे बैंकों को आने वाली तिमाही में बिजली क्षेत्र के कर्ज पर अपेक्षाकृत कम प्रावधान करना होगा।

नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार अक्षय ऊर्जा की अनिश्चित प्रकृति की वजह से अक्सर पारेषण प्रणाली पर कम क्षमता का उपयोग हो पाता है। इसकी वजह से वितरण कंपनियों को इस कमी की भरपाई और ग्रिड को स्थिरता प्रदान करने के लिए शेष बिजली खरीदनी होती है।

नई योजना के तहत ऊंची लागत वाली तापीय बिजली को सस्ती अक्षय ऊर्जा के साथ जोड़ने की अनुमति दी जाएगी, जिससे वितरण कंपनियों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस योजना के तहत बिजली उत्पादकों को सालाना बिजली आपूर्ति को 51 फीसदी अक्षय ऊर्जा के जरिये करनी होगी शेष आपूति तापीय ऊर्जा से की जाएगी।

बिजली क्षेत्र के कर्ज पर पहले ही बड़ा नुकसान झेल चुके बैंकों को उम्मीद है कि यह योजना बैंक परवान चढ़ेगी। पिछले हफ्ते भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई वाले कंसोर्टियम को सुजलॉन के 11,460 करोड़ रुपये के कर्ज पर 68 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ा था। बैंकों को जीवीके की पंजाब की परियोजना को डॉयचे बैंक को जीएमआर छत्तीसगढ़ परियोजना को अदाणी समूह को काफी कम कीमत पर बेचना पड़ा है। डॉयचे बैंक जिंदल इंडिया पावर के लिए भी 2,400 करोड़ रुपये की बोली लगाई है जबकि इस पर बैंकों को करीब 7,600 करोड़ रुपये का कर्ज है। करीब 26 गीगावाट क्षमता की 34 बिजली परियोजनाएं वर्तमान में ठप पड़ी हैं।

नई योजना के बोलीकर्ताओं को एनटीपीसी या भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ नए सिरे से 25 साल के लिए बिजली खरीद समझौता करने को कहा जाएगा। वे वितरण कंपनियों या थोक खरीदारों जैसे ग्राहकों के साथ बिजली आपूर्ति बिक्री समझौता (पीएसए) करेंगे। एसोसिएशन आफ पावर प्रोड्यूसर्स के महानिदेशक अशोक खुराना ने कहा कि इस योजना से समझौता न हुए ताप बिजली क्षमता के उपयोग में भी मदद मिलेगी। नई सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप बिजली संयंत्रों में कुछ ज्यादा रैंप रेट होता है, जिसका प्रभावी तरीके से इस्तेमाल अक्षय ऊर्जा के साथ 24 घंटे बिजली आपूर्ति में किया जा सकेगा।

खुराना ने कहा, 'इसमें सिर्फ हरित ऊर्जा पर ही जोर नहीं दिया जा रहा है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मिली जुली बिजली की आपूर्ति हो और ग्रिड की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। साथ ही ग्रिड के अधिकतम इस्तेमाल के साथ ग्राहकों को स्वच्छ ऊर्जा मुहैया कराई जा सके।' उन्होंने कहा, 'यह सबसे लिए मुनाफे का सौदा है।'

नई योजना सबके फायदे का सौदा

- फंसी परियोजनाओं को बहाल करने के लिए बिजली क्षेत्र के हिस्सेदारों की शुक्रवार को बैठक
- नई योजना के तहत अक्षय ऊर्जा को ताप बिजली के साथ जोड़ने का प्रस्ताव
- बोली के बाद बिजली उत्पादकों को नए बिजली खरीद समझौते पर करना होगा हस्ताक्षर
- नई योजना से बैंकों को ताप बिजली कंपनियों से कर्ज वसूलने में मिलेगी मदद

एचडीएफसी का लघु उद्योगों को कर्ज तीन साल में बढ़कर दोगुना

भाषा
मुंबई, 20 फरवरी

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक का लघु एवं मझोले (एसएमई) क्षेत्र को दिया गया कर्ज पिछले करीब तीन साल में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। यह दिसंबर 2019 में बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो मार्च 2017 में 74,000 करोड़ रुपये था।

इसके साथ बैंक की एसएमई के 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बाजार में 9 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हो गई है। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार जून 2019 तक एसएमई को दिया गया कुल कर्ज 15.7 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 10 प्रतिशत वृद्धि को बताता है।

एचडीएफसी बैंक एसएमई को कुल 1.48 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के साथ इस मामले में दूसरे पायदान पर आ गया है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 2.7 लाख करोड़ रुपये के एमएसएमई कर्ज के साथ दूसरे स्थान पर है। एसबीआई की एसएमई कर्ज खंड में बाजार हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत है।

बैंक ने मार्च 2017 से दिसंबर 2019 के दौरान 3 लाख नए ग्राहक जोड़े और खातों की संख्या 30.74 लाख से बढ़कर करीब 34 लाख हो गई। एचडीएफसी बैंक का एसएमई को दिए जाने वाले कर्ज में दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख (बिजनेस बैंकिंग) सुमंत रामपाल ने हाल में कहा था कि कुल 34 लाख ग्राहकों में से 30 प्रतिशत अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। ये एसएमई विनिर्माण, सेवा और निर्यात से जुड़े हैं।

रियल्टी परियोजनाएं पूरी करेगा एसबीआईकैप्स

अभिजित लेले
मुंबई, 20 फरवरी

- एसबीआईकैप्स **3,000** करोड़ रुपये के निवेश से **18** रियल्टी परियोजनाएं करेगा पूरा
- फंड के निवेश दल की बैठक **4** बार हो चुकी है और **18** अटकी परियोजनाओं पर काम हो रहा है
- इन **18** परियोजनाओं का कुल मूल्य **22,000** करोड़ रुपये

एसबीआई कैप्स वेंचर्स रियल एस्टेट फंड देश में अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संभावित 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से 18 परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

एसबीआईकैप वेंचर्स के मुख्य निवेश अधिकारी इरफान काजी ने कहा फंड के निवेश दल की बैठक चार बार हो चुकी है और 18 अटकी परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इन परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं जो नियमों को पूरा करने के अधीन है। इन 18 परियोजनाओं का कुल मूल्य 22,000 करोड़ रुपये है।

कुल 640 आवासीय इकाइयों वाले मुंबई और बंगलूरु स्थित एक-एक परियोजनाओं में धन का आवंटन जा चुका है। उन्होंने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर आयोजित एक रियल एस्टेट सम्मेलन से इतर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फंड की नजर देश भर की 300 परियोजनाओं पर है।

यह द्वितीय श्रेणी का वैकल्पिक निवेश फंड है जिसे सरकार की ओर से अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अंतिम चरण तक रकम मुहैया कराने के उद्देश्य से विशेष विंडो बनाने की घोषणा के तहत बनाया गया है। फंड का उद्देश्य सस्ती और मध्य आय वाली आवासीय परियोजनाओं को रकम मुहैया कराना है। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की सहायक इकाई एसबीआईकैप्स वेंचर्स और भारत सरकार फंड के लिए निवेश प्रबंधक हैं। फंड ने 10,530 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धताओं के साथ दिसंबर 2019 में अपना पहला क्लोजर पूरा किया था।

इस फंड में सरकार, एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी और दूसरे अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों ने पैसा डाला है।

आगे का निवेश संस्थागत और निजी निवेशकों के जरिये लाया जाएगा जिससे 25,000 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया जा सके। फंड में निवेश के लिए कंपनी सॉवरिन फंडों सहित कुछ वैश्विक निवेशकों से चर्चा कर रही है।

निरोगी राजस्थान, किसान, महिला, बच्चों व शिक्षा पर जोर

भाषा
जयपुर, 20 फरवरी

राजस्थान के सालाना बजट में निरोगी राजस्थान के साथ साथ किसानों की संपन्नता, महिला व बाल कल्याण पर जोर देते हुए कहा गया है कि सरकार पानी, बिजली व सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर ध्यान देगी। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है जबकि विभिन्न कर प्रस्तावों के माध्यम से लगभग 130 करोड़ रुपये की रियायतें दी गई हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 संकल्पों पर आधारित वित्त वर्ष 2020-21 का बजट गुरुवार को राज्य विधानसभा में पेश किया। गहलोत ने आगामी वित्त वर्ष में 53,181 नई भर्तियां करने की घोषणा की है। गहलोत ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार की राजस्व प्राप्तियां 1,73,404.42 करोड़ रुपये, राजस्व व्यय 1,85,750.03 लाख रुपये व राजस्व घाटा 12,345.61 करोड़ रुपये रहना अनुमानित है।

बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 33922.77 करोड़ रुपये रहना अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 2.99 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित बजटीय अनुमान भी सदन में पेश किए। गहलोत के बजट भाषण की मुख्य बातों का जिक्र किया जाए तो इसमें अगले वित्त वर्ष में 53,181 नई भर्तियां करने की घोषणा शामिल है जिसमें सबसे अधिक 41,000 भर्तियां शिक्षा विभाग में होंगी। इसके साथ ही गहलोत ने 100 करोड़ रुपये के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन, मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े कदमों के तहत एक प्राधिकरण व फास्ट्र ट्रैक अदालतें बनाने बनाने सहित कई प्रस्ताव किए गए हैं।

कर्जदाता की मंजूरी के लिए ई-वोटिंग की योजना

अमृता पिल्लई
मुंबई, 20 फरवरी

आईएलऐंडएफएस की 5 सड़क संपत्तियों के समाधान का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है क्योंकि इन परियोजनाओं की बोली की वैधता इस महीने के अंत तक खत्म हो रही है। इन संपत्तियों की बिक्री की आखिरी कवायद के तहत समूह अब ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से कर्जदाताओं की मंजूरी की मांग करेगा।

इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, '5 सड़क परियोजनाओं की बोली की वैधता 29 फरवरी को खत्म हो रही है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में आईएलऐंडएफएस की अगली सुनवाई की तिथि उसके पहले नहीं है, ऐसे में समूह ई वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से कर्जदाताओं की मंजूरी लेने की कवायद कर रहा है।' सूत्र ने कहा, 'इनमें से कुछ परियोजनाओं के लिए ई-वोटिंग की कवायद इस महीने की शुरुआत में की गई थी। सभी 5 परियोजनाओं के लिए यह प्रक्रिया अंतिम तिथि के पहले पूरी होने की उम्मीद है।'

आईएलऐंडएफएस के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि इन 5 परियोजनाओं के लिए ई-वोटिंग स्वीकार कर लिया गया है।

एक शपथपत्र में समूह द्वारा साझा किए गए विस्तृत ब्योरे के मुताबिक समूह ने बोलीकर्ताओं से संपर्क किया है और बोली की वैधता की तिथि बढ़ाने की मांग की है। बहरहाल बोलीकर्ताओं ने आशय पत्र जारी करने की समय सीमा को लेकर स्पष्टता न होने की स्थिति में ऐसा करने में अक्षमता जाहिर की है।

दिसंबर 2018 में एक सार्वजनिक बोली की प्रक्रिया की पहल 14 सड़क संपत्तियों की बिक्री के लिए की गई थी। अगस्त 2019 में समूह ने इन संपत्तियों में से 10 के लिए बोली हासिल की थी, जिसकी बोली का संयुक्त मूल्य करीब 13,000 करोड़ रुपये है। आईएलऐंडएफएस ने 10 परियोजनाओं में से सिर्फ 5 की बोली पर आगे बढ़ने का फैसला किया था, क्योंकि शेष की बोली बाजार के उचित मूल्य की तुलना में बहुत कम थी। अक्टूबर में नए प्रबंधन ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) मॉडल के मुताबिक 15 सड़क संपत्तियों में से शेष 9 के मुद्रीकरण का फैसला किया।

चेन्नई नशरी टनलवे, हजारीबाग रांची एक्सप्रेसवे, जोराबट शिलांग एक्सप्रेसवे, पुणे सोलापुर रोड डेवलपमेंट कंपनी और झारखंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन कंपनी 5 संपत्तियां हैं जिनमें बोली उचित बाजार भाव की तुलना में ज्यादा थी। उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी ने कहा, 'इन 5 परियोजनाओं के लिए बोली का कुल मूल्य 7,489 करोड़ रुपये है, जबकि कुल कर्ज 10,500 करोड़ रुपये है और उचित बाजार मूल्य 7,200 करोड़ रुपये है।' समूह अब कर्जदाताओं से अनुमति की मांग करक रहा है, जिससे इन 5 परियोजनाओं की बिक्री को बोली में तय तिथि बीतने से पहले अंतिम रूप दिया जा सके।

इस साल अक्टूबर महीने में सरकार की ओर से समूह के लिए नियुक्त प्रबंध समिति ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि कम से कम समूह के आधे कर्ज का समाधान, वसूली या पुनर्गठन कर लिया जाएगा और मार्च 2020 के पहले इसके बड़े हिस्से पर काम हो जाएगा। कर्जदाता की मंजूरी मिलने से आईएलऐंडएफएस के नए बोर्ड को समाधान प्रक्रिया में समय से कदम उठाने में मदद मिलेगी, जो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डीके जैन व अन्य नियामकीय मंजूरियां मिलने पर निर्भर होगा।

नई रणनीति

- सड़क संपत्तियों की बोली की वैधता की तिथि समाप्ति के करीब होने पर आईएलऐंडएफएस ने बनाई योजना
- 5 सड़क परियोजनाओं की बोली की वैधता 29 फरवरी को खत्म हो रही है
- राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में आईएलऐंडएफएस की अगली सुनवाई की तिथि उसके पहले नहीं
- दिसंबर 2018 में 14 सड़क संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक बोली की प्रक्रिया की पहल की गई थी

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 5

राजस्व लक्ष्य की समस्या

यह देश के राजकोषीय प्रबंधन का एक नियमित गुण बन चुका है। पहले सरकार राजस्व के लिए एक अतिमहत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय करती है और जब वह तय लक्ष्य से बुरी तरह पिछड़ जाती है तो कर अधिकारियों का दबाव शुरू हो जाता है। वर्ष 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी दल पर 'कर आतंकवाद' का आरोप लगाकर बार-बार हमले किए। उसका कहना था कि इससे न केवल कारोबारी वर्ग पर नकारात्मक असर पड़ता है बल्कि देश की छवि पर भी बुरा असर होता है। परंतु छह वर्ष बाद भी यह परंपरा जारी है।

समाचार पत्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कर विभाग अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के निदेशकों को भी नोटिस`ज रहा है। उन्हें बकाये का जिम्मेदार बताया जा रहा है। हाल के सप्ताहों में ऐसे नोटिस की तादाद तेजी से बढ़ी है। मांगी गई राशि भी 5 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये के बीच है। कुछ मामलों में निदेशकों को उक्त राशि चुकाने के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया गया है। उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 179 के तहत जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे मामलों में यदि निदेशक तय समय में राशि चुकाने में नाकाम रहे तो निदेशकों के बैंक खाते और उनकी परिसंपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। हालांकि उक्त धारा समाप्त होने की प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों के लिए है लेकिन इसे सभी कंपनियों पर लागू किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक निदेशकों के पास केवल यही रास्ता है कि वे यह साबित कर दें कि रिकवरी नहीं हो पाने का कारण उनकी अनदेखी या विश्वास भंग नहीं है।

ऐसे कर नोटिस और परिसंपत्ति को कुर्क किए जाने की संभावना लोगों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में निदेशक की भूमिका अपनाने से रोकेगी। गौरतलब है कि देश में कुल कंपनियों में 95 फीसदी ऐसी ही हैं। कर विभाग के कदम सरकार के कारोबारी सुगमता बढ़ाने के घोषित लक्ष्य से उलट हैं। ऐसे नोटिस कर संबंधी कानूनी मामले कम करने के लक्ष्य के भी खिलाफ हैं। सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपये के कर विवादों को हल करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। असंगत कर मांग से केवल कानूनी मामले बढ़ेंगे और कारोबारी माहौल प्रभावित होगा।

बहरहाल, कर नोटिस की वास्तविक वजह बजट में तलाश की जा सकती है। चालू वित्त वर्ष के राजस्व लक्ष्य में काफी कमी किए जाने के बावजूद सरकार के लिए उसे हासिल कर पाना मुश्किल है। उसे चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में शुद्ध कर राजस्व का 40 फीसदी जुटाना होगा। गत वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में केवल 30 फीसदी शुद्ध कर राजस्व जुटाया जा सकेगा। सरकार ने पहले ही राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में बचाव की राह ले ली है। ऐसे में वह राजकोषीय घाटे को और बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। यदि कर संग्रह लक्ष्य से कम रहता है तो उसे व्यय में और कटौती करनी होगी या उसे आगे बढ़ाना होगा।

ज्यादा बुरी बात यह है कि अगले वर्ष भी हालात बदलते नहीं नजर आते। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 12 फीसदी राजस्व वृद्धि का लक्ष्य तय किया है जो अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी है। साल दर साल उसी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय अहम यह है कि सरकार राजस्व के वास्तविक अनुमान तय करे और व्यय को उसके अनुसार समायोजित करे। अवास्तविक लक्ष्यों के साथ कर विभाग पर दबाव बनाने से न केवल करदाता प्रताड़ित होंगे बल्कि कारोबारी माहौल भी प्रभावित होगा। कहने का अर्थ यह नहीं है कि सरकार अपना उचित बकाया न वसूले। परंतु राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सत्ता और कानून का गैरवाजिब इस्तेमाल कारोबारी जगत को हतोत्साहित करता है।

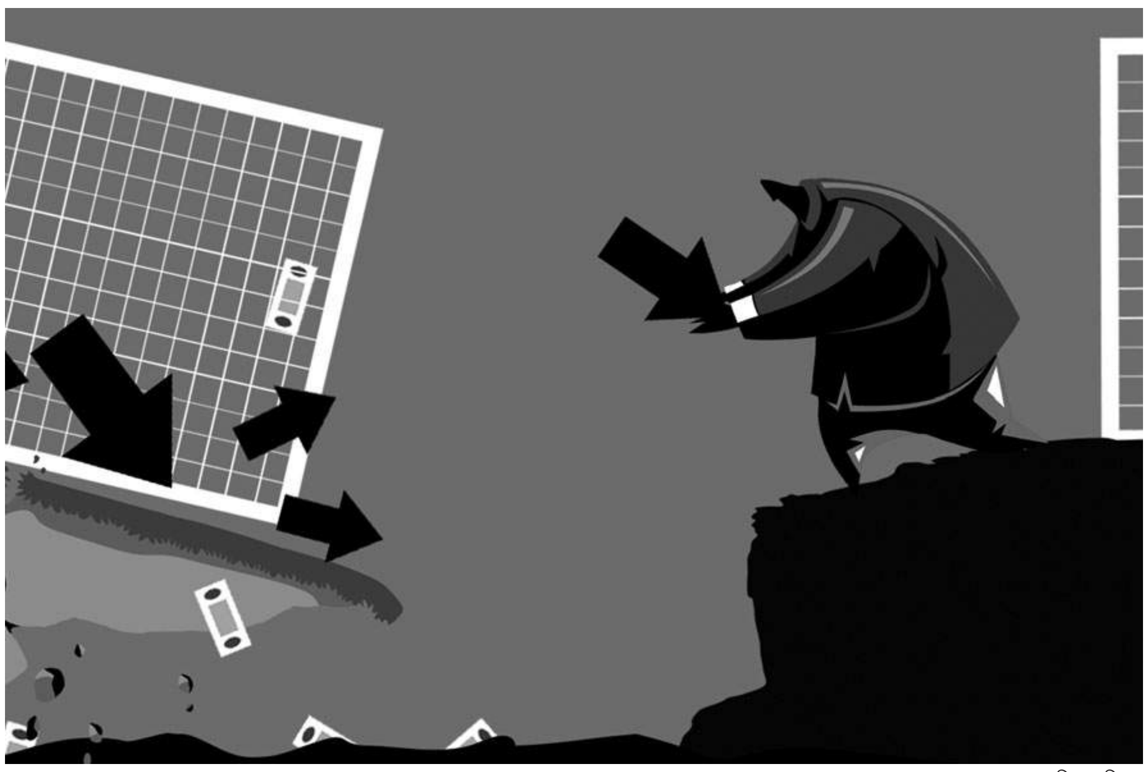

विनय सिन्हा

अर्थव्यवस्था की स्थिति और बाजार के संकेत

भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के रुख के अनुमानों की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि संकीर्ण शेयर बाजार सूचकांक इन अनुमानों से कहीं दूर हो सकते हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **नीलकंठ मिश्रा**

व्यापक तौर पर यह माना जाता है कि शेयर बाजार अर्थव्यवस्था का एक अग्रगामी संकेतक है। हालांकि ऐसा व्यक्ति तलाश करना मुश्किल है जो भविष्य को लेकर संपूर्ण दृष्टि रखता हो। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बाजार कई व्यक्तियों का एक 'न्यूट्रल नेटवर्क' होता है। ये तमाम लोग शेयरों के सामूहिक क्रय-विक्रय के आधार पर आर्थिक रुझान को परिलक्षित करते हैं। ये रुझान कई बार वास्तविक घटनाक्रम के महीनों या वर्षों पहले भी देखने को मिल सकते हैं। लोग मानते हैं कि यह सामूहिक सबक, व्यक्तिगत प्रतिभागियों से कहीं अधिक बेहतर होता है।

यह बात बहुत आकर्षक प्रतीत होती है और हममें से जिन लोगों ने बाजार में लंबा समय बिताया है, उनके दिमाग में ऐसे कई उदाहरण आएंगे जहां शेयर कीमतें बुनियादी बदलावों से आगे चलती रहीं और लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। इसके साथ ही पुराने लोगों को यह भी याद होगा कि कई बार कीमतें असंगत रूप से ऊंची या नीची हो जाती हैं, लोगों में हड़बड़ी भी देखने को मिलती है। प्रश्न यह है कि कमजोर आर्थिक गति और शेयर कीमतों में इजाफे की मौजूदा असंगति को किस प्रकार देखा जाए? क्या बाजार का इशारा आर्थिक सुधार की ओर है या फिर वे जल्दी आर्थिक कमजोरी दर्शाने लगेंगे और उनमें सुधार होगा?

फिलहाल यह याद रखना उचित होगा कि शेयर बाजार का गठन अर्थव्यवस्था से अलग है। इसे दर्शाने के लिए हम शीर्ष 500 शेयरों को चार श्रेणियों में बांटते हैं: वैश्विक, वृहद, पहुंच और बाजार हिस्सेदारी। वैश्विक शेयरों की बात करें तो बुनियादी शेयर वैश्विक रुझान से संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए धातु, तेल रिफाइनरी, औषधि निर्यातक, और भारत में सूचीबद्ध वैश्विक वाहन कंपनियां आदि। वृहद श्रेणी के शेयर वे शेयर हैं जिन पर घरेलू आर्थिक वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इनमें औद्योगिक कंपनियों के शेयर, सरकारी बैंकों के शेयर, सीमेंट और अन्य उपयोगी वस्तुओं के शेयर शामिल हैं। पहुंच वाली श्रेणी में वे कंपनियां हैं जो बेहतर वितरण तथा अन्य कारकों के कारण औपचारिक अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से विकसित होती हैं। मसलन बीमा और वातानुकूल संयंत्रों की मांग कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद बेहतर बनी रही। बाजार हिस्सेदारी की बात करें तो निजी बैंक बैंक ऋण न बढ़ने के बावजूद दो अंकों में बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी बैंकों से बाजार हिस्सेदारी छिन रही है। इससे पता चलता है कि बाजार पूंजीकरण के पांचवें हिस्से से भी कम वृहद श्रेणी में है। यह बात शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था की असंगतता को रेखांकित करती है।

पूंजी की आवक भी शेयर कीमतों पर असर डालती है। सैद्धांतिक तौर पर ऐसा लंबे समय तक नहीं होना चाहिए और अग्रगामी आय की भी भूमिका होनी चाहिए। बाजार प्रतिभागियों का फंड का इस्तेमाल करने या न करने का निर्णय भी बाजार से जुड़े अनुमानों से प्रभावित होना चाहिए। ऐसे में घरेलू म्युचुअल फंड में तेज आवक के अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बीते 12 महीनों में इन्होंने 16 अरब डॉलर की खरीद की है जो चार वर्ष के उच्चतम स्तर पर है। देश की आर्थिक वृद्धि के अनुमानों में तेज गिरावट के बावजूद ऐसा हुआ है। यह रुझान जल्द बदलता नहीं दिखता।

इसे समझने के लिए हमें शेयर बाजार के स्वामित्व की प्रकृति पर नजर डालनी होगी: इसके आधे हिस्से पर प्रवर्तक काबिज हैं। इसमें सरकारी और निजी दोनों तरह के प्रवर्तक शामिल हैं। शीर्ष 500 शेयरों का विदेशी स्वामित्व दिसंबर 2019 में 21.2 फीसदी के साथ 30 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसका पांचवां हिस्सा सॉवरिन वेल्थ फंड्स, विदेशी केंद्रीय बैंकों और पेंशन फंड के पास है। भारत में इन फंड का एक मानक आवंटन है और वे आवक पर भी नजर रखते हैं। पांचवां हिस्सा हेज फंड जैसे व्यापक फंडों के पास और आधा म्युचुअल फंड के पास है। ये इक्विटी सूचकांक के मानक हैं और इनमें भारतीय हिस्सेदारी अवश्य है। जब वैश्विक शेयर बाजार की मजबूती की बदौलत इन मानक फंड में आवक होती है तो कम से कम कुछ हिस्सा भारत पहुंचता है। यदि फंड प्रबंधक भारत की संभावनाओं को बेहतर न मानें तो भारत का दबदबा कम हो सकता है। भारत के समर्पित फंड धन जुटाने में संघर्ष करते रहे हैं। बीते पांच वर्ष में एफपीआई खरीद का बड़ा हिस्सा वित्तीय रहा है। इनमें अभी भी मजबूत आय वृद्धि हो रही है।

शेयर बाजार का घरेलू संस्थागत स्वामित्व रिकॉर्ड स्तर पर है क्योंकि म्युचुअल फंड में अच्छी आवक हो रही है। शेयर में यह वृद्धि सरकार के खर्च पर हुई है। उसकी हिस्सेदारी 8 फीसदी के निचले स्तर पर है। दशक भर पहले यह 28 फीसदी पर थी। ऐसा मोटे तौर पर सरकारी शेयरों के कमजोर प्रदर्शन और उसकी हिस्सेदारी की बिकवाली से हुआ। शेयरों का खुदरा स्वामित्व भी 14.2 फीसदी के निचले स्तर पर रहा, हालांकि यहां गिरावट अधिक गहरी है। हमारे विश्लेषकों के मुताबिक ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बचतकर्ता परिसंपत्तियों को प्रबंधित पोर्टफोलियो से म्युचुअल फंड में ले जा रहे हैं।

ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे और मिड-कैप फंड के प्रबंधन वाली परिसंपत्ति अब तक के उच्चतम स्तर पर है। यह 15 माह पहले के स्तर से 29 फीसदी ऊंचाई पर है। ऐसा छोटे और मिड-कैप शेयरों में कमजोरी के बावजूद है। एफपीआई का ध्यान बड़े और नकदीकृत शेयरों पर है। उल्लेखनीय है कि घरेलू म्युचुअल फंड के लिए भी निष्क्रिय फंड अब एयूएम के 15 फीसदी के लिए उत्तरदायी हैं। चार वर्ष पहले यह शून्य के करीब था।

निवेशक इन फंडों का चयन प्रबंधन शुल्क बचाने और बाजार पर लंबी अवधि का दांव लगाने के लिए करते हैं। इन फंड को ईपीएफओ से भी मदद मिलती है। ऐसी आवक 200 से 500 शेयरों वाले सूचकांक के बजाय 30 से 50 शेयरों वाले सूचकांक की जमीन तैयार करती है। छोटे और मिड-कैप शेयर दो वर्ष से कमजोर रहे लेकिन जनवरी में उन्होंने जबरदस्त वापसी की। परंतु फरवरी में एक बार फिर उनमें गिरावट का दौर शुरू हो गया है जो जारी रह सकता है।

घरेलू अर्थव्यवस्था लार्ज-कैप शेयरों के बजाय छोटे और मिड-कैप शेयरों के मामले में अधिक जोखिम में है। उनका स्वामित्व भी घरेलू है इसलिए वे विदेशी फंड प्रवाह से प्रभावित नहीं होते। जो लोग शेयर बाजार की ओर से अर्थव्यवस्था को मिलने वाले अग्रगामी संकेतों की ओर देख रहे हैं, उनके लिए छोटे और मझोले शेयरों का प्रदर्शन भविष्य का बेहतर संकेतक हो सकता है, बजाय कि संकीर्ण और कहीं अधिक लोकप्रिय सूचकांकों की तुलना में।

सर्वोच्च अदालत में याचिकाओं की भरमार, उपाय की दरकार

अदालती आईना

एम जे एंटनी

उच्चतम न्यायालय का पूर्व अवतार फेडरल कोर्ट तभी बैठता था जब उसके समक्ष कोई मामला आता था। उसके पास कभी-कभार ही कोई मामला पहुंचता था। जब 1950 में उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ तो उसके पास आने वाले मामलों की संख्या बहुत कम थी। वे ऐसे छपते थे जैसे दिल्ली के कुछ अखबारों में आने वाले कार्यक्रमों के विज्ञापन।

लेकिन अब समय बदल चुका है। अब मामले सैकड़ों पन्नों में छपते हैं और 16 कमरों में 34 न्यायाधीश सुनवाई करते हैं। वकीलों की संख्या 50 गुना बढ़ गई है। इससे न्यायालय के गलियारों और कमरों में भीड़भाड़ बढ़ गई है। मुख्य न्यायाधीश और अटॉर्नी जनरल ने पिछले सप्ताह सवाल उठाया कि क्या 1958 में बना उच्चतम न्यायालय का मौजूदा परिसर जगह की कमी के दबाव को झेल सकता है। उन्होंने एक नया परिसर बनाने की संभावना पर भी चर्चा की। माना जा रहा है कि न्यायालय एक फर्म से भी सलाह मशविरा कर रहा है जिसे सार्वजनिक इमारतों में भीड़ के प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल है।

शीर्ष न्यायालय पर दबाव के पीछे कई कारण हैं। इसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है। 2019 में दिए गए 1,293 फैसलों के विश्लेषण से इसका संकेत मिलता है। उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक अदालत माना जाता है लेकिन उसने पिछले वर्ष जिन मामलों में फैसला सुनाया, उनमें से केवल 43 मामले (3.3 फीसदी) ही प्रत्यक्ष तौर पर संविधान से जुड़े थे। इसकी तुलना में 188 फैसले सरकारी नौकरियों से जुड़े थे। ये चयन, तबादला, प्रोन्नति, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे मामूली मुद्दों से जुड़े थे। इनसे निपटने के लिए प्रशासनिक पंचाट और अपील संस्थाएं हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। फैसले से असंतुष्ट लोगों के लिए समीक्षा और सुधारात्मक याचिका का भी विकल्प है। सशस्त्र सेनाओं के पंचाटों के खिलाफ अपील भी उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे 35 मामलों में फैसला सुनाया जो रक्षा बलों में विषमताओं की ओर इशारा करते हैं।

हालांकि देश में एक व्यापक मध्यस्थता एवं सुलह कानून है जो कई बार संशोधित हो चुका है। लेकिन इस मुद्दे पर भी 53 फैसले दिए गए। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया कानून ने उच्चतम न्यायालय का अधिकांश बोझ ले लिया है लेकिन शीर्ष न्यायालय ने कंपनी कानून, बैंकिंग और बुनियादी ढांचे से जुड़े 31 मामलों में फैसला सुनाया। इसी तरह 38 फैसलों में श्रम कानून से जुड़े सवालों का निपटारा किया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े फैसलों की संख्या 36 थी। 63 मामलों में भूमि अधिग्रहण, हदबंदी कानूनों और भूमि सुधार कानूनों के तहत विवादों का निपटारा किया गया।

न्यायालय ने साथ ही किरायेदार और मकान मालिक से जुड़े 27 विवादों में फैसला दिया। हरित पंचाटों की स्थापना के बाद पर्यावरण से जुड़े मामलों की संख्या घटकर 20 रह गई है।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सबसे अधिक 324 फौजदारी मामलों का निपटारा किया। इनमें से अधिकांश अपील हत्या, घरेलू हिंसा, यौन हमला, किशोरों से जुड़े अपराध, अनुसूचित जाति/जनजाति, भ्रष्टाचार, एहतियाती हिरासत और जमानत से जुड़े थे। इन अपीलों में तथ्यों से जुड़े सवाल उठाए गए थे और आमतौर पर इन्हें उच्चतम न्यायालय तक नहीं पहुंचना चाहिए लेकिन निचले स्तर पर न्याय की खराब गुणवत्ता और कानूनी पेशे की प्रवृत्ति के कारण ऐसे मामले शीर्ष न्यायालय में पहुंच जाते हैं। विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि जनहित याचिका से अदालत पर बोझ बढ़ा है और व्यक्तिगत याचियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि बेतहाशा ऐसे मामले दायर किए जा रहे हैं। लेकिन केवल 18 जनहित याचिकाओं में ही फैसले दिए गए जो उनकी धारणा के अनुकूल नहीं है। जनहित याचिकाओं पर फैसलों से समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा होता है। रिट अदालतों में भविष्य में और बोझ पड़ना तय है। इसलिए नहीं कि हर बजट में उनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त राशि आवंटित नहीं की गई बल्कि इसलिए भी कि साक्षरता और कानून के बारे में जानकारी बढ़ रही है। देश में जारी मौजूदा राजनीतिक माहौल में दुकानों में संविधान की प्रतियों की बिक्री बढ़ गई है। प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों को पढ़ना विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बन गया है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन की जगहों पर पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं। मौलिक अधिकार स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। व्यावसायिक फिल्मों में कानूनी विषयों को उठाया जा रहा है और सेक्शन 375 जैसी फिल्में बनाई जा रही हैं। जब लोग संविधान पढ़ना शुरू करते हैं तो अदालतों में इस पर लंबी बहस होती है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा है जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और 120 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। अगर अदालत कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग यानी सीधे प्रसारण की अनुमति दे दे तो भरमार कुछ कम हो सकती है। न्यायाधीश विशेष अनुमति याचिकाओं की संख्या पर भी लगाम लगा सकते हैं जिन्हें आसानी से स्वीकार किया जाता है। कई मामलों में तो उच्च न्यायालय के स्तर पर ही निपटारा हो जाना चाहिए। इससे न्यायालय को कई दशकों से लंबित करीब 60 संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए कुछ समय मिल जाएगा।

> अगर अदालत कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग यानी सीधे प्रसारण की अनुमति दे दे तो भरमार कुछ कम हो सकती है। न्यायाधीश विशेष अनुमति याचिकाओं की संख्या पर भी लगाम लगा सकते हैं जिन्हें आसानी से स्वीकार किया जाता है

कानाफूसी

वाजिब शिकायत

मोबाइल नेटवर्क में कमी को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतों में नया कुछ भी नहीं है। परंतु इन दिनों जैसा दौर चल रहा है, कोई भी बात बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण होकर उभरती है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जहां दूरसंचार विभाग को अपना समायोजित सकल राजस्व का बकाया चुकाने के लिए जूझ रहे हैं, वहीं पिछले दिनों एक दूरसंचार अधिकारी को दूरसंचार विभाग के गलियारे में हताश देखा गया। फोन पर बात करने के लिए बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि दूरसंचार कार्यालय में ही फोन नहीं लग पा रहा है। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो विभाग ने समायोजित सकल राजस्व चुकता करने को लेकर अपना रुख नरम किया है लेकिन अगर लोगों को फोन पर बात करने में ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो यह तो एक वाजिब शिकायत है।

आईटीसी की चांदी

कारोबारी अक्सर किसी कंपनी के बारे में सकारात्मक खबर फैला कर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसा करने से कंपनी के शेयरों की कीमत में उछाल आने की संभावना रहती है। हाल के दिनों में उनमें से कुछ ने आईटीसी को लेकर सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया है। दरअसल बजट के बाद से ही कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली क्योंकि बजट में सिगरेट पर लगने वाला कर बढ़ाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा भी आईटीसी के लिए सकारात्मक बात है। इससे पहले चार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा के दौरान दिल्ली में आईटीसी के मौर्या होटल में रुके हैं। इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। इन दिनों वायरल हुए एक एसएमएस पर यकीन करें तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने अपने प्रतिनिधिमंडल के लिए पूरा होटल बुक कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति 14वीं मंजिल पर स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकेंगे।

आपका पक्ष

शाहीन बाग बंद रास्ते का समाधान कब

दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले दो माह से सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों की वजह से आम लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। इस सड़क को खाली कराने के लिए अदालत में याचिका भी डाली गई है। अदालत ने सड़क खाली कराने तथा प्रदर्शनकारियों को वैकल्पिक जगह भेजने के आदेश भी दिए हैं। इसके बावजूद सड़क खाली नहीं हो पाई है। इस दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्ला खान ने अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार से 75 हजार वोटों से विजयी प्राप्त की। इस पूरे मामले को चुनाव से पूर्व तक राजनीतिक मामला बना दिया गया था। कई दलों ने शाहीन बाग को मुद्दा भी बनाया। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली और केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन शाहीन बाग का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। शाहीन बाग में सड़क बंद होने की वजह से सबसे अधिक परेशानी नोएडा और दिल्ली के बीच सफर करने वाले लोगों को हो रही है। नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले कालिंदी कुंज मार्ग को प्रदर्शन के कारण बंद कर दिया गया है। जब तक शाहीन बाग में प्रदर्शन खत्म नहीं होता तब तक नोएडा और दिल्ली आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस मार्ग पर लोगों को पिछले दो माह से अधिक समय से अपने गंतव्य जाने में घंटों लग रहे हैं। लोगों को समय के साथ अधिक किराया भी लग रहा है। अत: केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार तथा देश की सर्वोच्च अदालत को इस सड़क को खाली कराने के लिए सख्त रवैया अपनाने चाहिए। सरकार के ढुलमुल रवैये से पिछले दो माह से लोग हटने से इनकार ही कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की आस अब अदालत से ही बनी हुई है। सड़क खाली कराने के लिए पुलिस को कड़े निर्देश देने की आवश्यकता है जिससे प्रदर्शनकारियों को अन्य जगहों पर भेजा जा सके।

रीमा सिंह, नई दिल्ली

शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दो माह से प्रदर्शन चल रहा है

शादी समारोह में कम खर्च करें

शादी या पर्व-त्योहारों पर दिखावे का फैशन चल पड़ा है। कुछ समय पहले शादियों में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने सुझाव दिया था कि चाय और नमकीन में भी फेरे लेकर विवाह की रस्म निभाई जा सकती है। इसके लिए लाखों रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है। कुछ लोग विवाह में इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं कि बाद में उनके घर का सारा बजट बिगड़ जाता है। अमीर लोगों को लाखों रुपये खर्च करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधारण कमाई करने वाला और गरीब अगर विवाह में लाखों रुपये खर्च करे तो वह सारी जिंदगी गरीबी से उबर नहीं सकेगा। अगर विवाह समारोहों में फिजूलखर्ची पर सख्त कानून बना दिए जाएं तो काफी राहत मिलेगी। लोगों को भी चाहिए कि वे विवाह समारोहों में उतना ही खर्च करें जितनी उनकी हैसियत होती है। लोगों की निंदा या ताने के डर से अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ही समस्या लेकर आता है। शादियों में खाने की बरबादी को भी रोकने की आवश्यकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

कोरोनावायरस से हीरा उद्योग परेशान

एजेंसियां
मुंबई, 20 फरवरी

चीन और हॉन्गकॉन्ग के कुछ इलाकों में कोरोनावायरस के कहर के कारण रेटिंग एजेंसी इक्रा ने हीरा तराश उद्योग के लिए परिदृश्य स्थिर से नकारात्मक कर दिया है।

इक्रा ने एक रिपोर्ट में कहा कि कोरोनावायरस के प्रभाव और प्रमुख बाजारों में कमजोर मांग के कारण हीरा तराश उद्योग पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है। तराशे हुए हीरों की कुल खपत में चीन की 14 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि भारत में तराशे गए हीरों का 35 फीसदी हिस्सा हॉन्ग कॉन्ग के रास्ते निर्यात होता है।

इक्रा के वाइस प्रेजिडेंट (कॉरपोरेट रेटिंग्स) जय सेठ ने कहा, चीन के हालिया घटनाक्रम के अलावा हीरा तराश उद्योग अहम बाजारों में कमजोर मांग की समस्या से जूझ रहा है। तैयार माल की कीमतों में गिरावट के कारण उनके मुनाफे पर भी भारी दबाव है। अगर चीन और हॉन्गकॉन्ग में यही स्थिति रहती है तो उद्योग की स्थिति और बदतर होगी और उसका नकदी प्रवाह प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि इसके उद्योग के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कंपनियों का क्रेडिट प्रोफाइल भी प्रभावित हो सकता है।

सेठ ने कहा कि चीन में कोरोनावायरस के कहर के कारण तराशे हुए हीरों की वैश्विक मांग प्रभावित हो सकती है। इसी तरह चीन और हॉन्गकॉन्ग में आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से मांग के पटरी पर लौटने में समय लगेगा। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार युद्ध और राजनीतिक तनाव के कारण पहले से ही हीरा उद्योग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पामोलिन आयात के फिर लाइसेंस

11 लाख टन रिफाइंड पामोलिन होगा आयात, इंडोनेशिया से मंगाने की इजाजत

रॉयटर्स
मुंबई /नई दिल्ली, 20 फरवरी

- भारत ने इसका आयात एक माह पहले सीमित किया था, अब लाइसेंस जारी करने पर उद्योग जगत हैरान हैं
- भारत द्वारा रिफाइंड पामोलिन खरीद की दोबारा शुरुआत करने से देश के कुल पाम तेल आयात में इजाफा हो सकता है
- भारत ने 8 जनवरी को रिफाइंड पाम तेल और पामोलिन को सीमित वस्तुओं की सूची में डाला था
- कश्मीर मसले और नए नागरिकता कानून की आलोचना के बाद मलेशिया के खिलाफ भारत ने जवाबी कदम उठाया था

भारत ने इंडोनेशिया से 11 लाख टन रिफाइंड पामोलिन का आयात करने के लिए लाइसेंस आवंटित किए हैं। सरकार और व्यापारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस कदम से उद्योग हैरान है क्योंकि केवल एक महीने पहले ही भारत ने इस जिंस का आयात सीमित कर दिया था।

दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल आयातक भारत द्वारा रिफाइंड पामोलिन खरीद की दोबारा शुरुआत करने से देश के कुल पाम तेल आयात में इजाफा हो सकता है और मलेशिया के पाम तेल के वायदा में मदद मिल सकती है। भारत ने 8 जनवरी को रिफाइंड पाम तेल और पामोलिन को सीमित वस्तुओं की सूची में डाल दिया था। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर मसले और नए नागरिकता कानून की आलोचना के बाद शीर्ष आपूर्तिकर्ता मलेशिया के खिलाफ यह जवाबी कदम उठाया गया था।

इस कदम ने रिफाइंड पामोलिन का आयात करने के लिए कारोबारियों को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से अनुमति लेने के लिए प्रेरित किया था और वाणिज्य मंत्रालय की इस शाखा को लाइसेंस के लिए 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।

एक सरकारी अधिकारी और तीन व्यापारियों ने रॉयटर्स को बताया कि डीजीएफटी ने व्यापारियों के इन आवेदनों के आधार पर उन्हें 11 लाख टन रिफाइंड पामोलिन का आयात करने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत ने केवल इंडोनेशिया से रिफाइंड पामोलिन आयात के लिए अनुमति प्रदान की है।

कश्मीर और नए नागरिकता कानून के संबंध में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहमद द्वारा आलोचना किए जाने के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में भारत ने निजी रूप से पाम तेल आयातकों से मलेशिया के उत्पादों का बहिष्कार करने का आग्रह किया था।

लाइसेंस प्राप्त करने वाले एक कारोबारी ने कहा कि अपने आवेदन में आयातकों को 'मूल उत्पत्ति वाले देश' का उल्लेख करना जरूरी था और सभी ने इंडोनेशिया का उल्लेख किया। कारोबारी ने कहा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने मूल उत्पत्ति वाले देश के रूप में मलेशिया का उल्लेख किया हो। मैं कुछ अन्य लोगों को जानता हूं जिन्होंने इंडोनेशिया का उल्लेख किया है।

> डीजीएफटी ने व्यापारियों के आवेदनों के आधार पर उन्हें 11 लाख टन रिफाइंड पामोलिन का आयात करने के लिए लाइसेंस जारी किया

लाइसेंस आवंटन ने उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को हैरान कर दिया है। मुंबई स्थित व्यापारिक संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा कि बड़े स्तर पर रिफाइंड पामोलिन आयात को अनुमति देने से इस जिंस को सीमित सूची में रखने का उद्देश्य विफल हो गया है।

भारत का खाद्य तेल उद्योग स्थानीय रिफाइनिंग को बढ़ावा देने के लिए रिफाइंड पाम तेल का आयात रोकने की मांग कर रहा है। बुधवार को उद्योग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़े पैमाने पर रिफाइंड पाम तेल आयात की अनुमति दिए जाने पर नाराजगी जताई और डीजीएफटी अधिकारियों को ज्यादा लाइसेंस आवंटित नहीं करने के लिए कहा है। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले एक व्यापारी ने यह जानकारी दी।

एक अन्य सरकारी अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछेक सप्ताह के दौरान खाद्य तेल के दामों में तेजी ने भारत को आयात नीति में परिवर्तन के लिए प्रेरित किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने अधिक जानकारी देने के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया।

एसईए ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी में भारत का पाम तेल आयात पिछले साल की तुलना में 27 प्रतिशत घटकर 5,94,804 टन रह गया। रिफाइंड पाम तेल आयात पर प्रतिबंध के कारण भी इस पर असर पड़ा है। भारत ने 31 अक्टूबर को समाप्त हुए विपणन वर्ष के दौरान 94 लाख टन पाम तेल का आयात किया है जिसमें 27.2 लाख टन रिफाइंड पाम तेल भी शामिल है।

भारत के कुल खाद्य तेल आयात में पाम तेल का हिस्सा लगभग दो-तिहाई रहता है। भारत पाम तेल मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से खरीदता है, जो दुनिया के क्रमश: पहले और दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश हैं।

चांदी की मांग और आयात कम, लेकिन दामों में दम

राजेश भयानी
मुंबई, 20 फरवरी

भारत में चांदी का कुल तिमाही आयात केवल 500 टन रहा जो पिछले साल से काफी कम है

अगर औद्योगिक मंदी और चीन का कोरोनावायरस और फैलता है, तो सोने से उलट कम दाम वाली मूल्यवान धातु चांदी के संबंध में वर्ष 2020 के दौरान निवेशकों को प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता वर्ष 2020 में इसकी कीमतों में तेजी आने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि भारत इस सफेद धातु का आयात कम करेगा। हालांकि सोने की तरह ही भारत इसका कम ही आयात कर रहा है, लेकिन घरेलू मांग में भी गिरावट आ रही है और बाजार में चांदी का पुराना स्टॉक बेचा जा रहा है।

अगर चीन का वायरस फैलने से हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तथा वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचता है, तो इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक धातुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है जिसका असर चांदी पर भी पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि चांदी की ज्यादा मांग औद्योगिक उपयोगकर्ताओं की ओर से होती है जो मंदी और चीन के वायरस से दबाव में हैं, जबकि भारत जैसा बड़ा उपभोक्ता देश चांदी की खरीद भी कम कर रहा है। दूसरी ओर सोने के दामों में तेजी देखी गई है जो प्रति औंस करीब 1,600 डॉलर के स्तर पर चल रहा है और इसमें तेजी जारी रहने की संभावना है। इससे चांदी को फायदा पहुंचेगा। खास तौर पर पिछले साल जुलाई में आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने और दामों के बढ़ने से भारत की मांग नरम रही है। इसके परिणामस्वरूप दिसंबर तिमाही के दौरान भारत में इस सफेद धातु का कुल तिमाही आयात केवल 500 टन ही रहा। पिछले कई सालों से आयात का इतना कम स्तर नहीं देखा गया था।

जीएफएमएस के सराफा विश्लेषक देवजित शाह ने कहा कि दिसंबर 2019 में आयात सालाना आधार पर 79 प्रतिशत की भारी-भरकम गिरावट के साथ 503 टन रहा, जबकि कुल मांग में केवल नौ प्रतिशत तक की ही गिरावट आई। बढ़ते दामों ने निवेशकों को अपने उस स्टॉक में कुछ कमी करने का मौका उपलब्ध कराया जिसे उन्होंने पहले से खरीद रखा था। उस समय दाम 40,000 रुपये के स्तर पर थे। इससे विदेशों से इस धातु की नई खरीद में कमी आई।

वर्ष 2018 में चांदी का आयात 6,958 टन था जो कम होकर करीब 5,700 टन रहने का अनुमान है। देवजित ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस साल आयात में वर्ष 2019 के स्तर की तुलना में कम से कम 15 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। जहां तक मांग पक्ष की बात है, तो हमें उम्मीद है कि कुल मांग में कम से कम पांच प्रतिशत तक की कमी आएगी।

देवजित को लगता है कि मांग में सुधार केवल तभी हो सकता है जब भारत में मौजूदा दाम 46,000 से 47,000 रुपये प्रति किलोग्राम से गिरकर 42,000 रुपये के स्तर पर आ जाएं। लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि चांदी के दाम ज्यादा रहने का अनुमान है।

वाशिंगटन स्थित उद्योग के हितधारकों के संगठन सिल्वर इंस्टीट्यूट ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि वर्ष 2019 में चांदी के दाम चार प्रतिशत बढ़कर 16.21 डॉलर प्रति औंस थे। वर्ष 2020 में चांदी का परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है। इसके वार्षिक औसत दाम 13 प्रतिशत तक बढ़कर छह साल के शीर्ष स्तर 18.40 डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। संस्थान ने प्रतिकूल परिस्थितियों पर भी जोर देते हुए कहा है कि यह तेजी मुख्य रूप से सोने के सकारात्मक प्रभाव के आधार पर है क्योंकि इस पीली धातु को नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में भू-राजनीतिक चिंताओं और व्यापक आर्थिक नीतियों से फायदा मिलना जारी रहेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंताओं का औद्योगिक धातुओं पर संभावित रूप से नकारात्मक असर पड़ेगा जो बढ़कर चांदी पर भी असर डालेगा। हालांकि अपेक्षाकृत छोटे बाजार के संस्थागत धन का दबाव सोने को पछाड़ते हुए चांदी के लिए पर्याप्त साबित होना चाहिए और इस कारण इस साल आगे चलकर सोने-चांदी का अनुपात कम होकर 70 के आस-पास जा सकता है।

सोने-चांदी का अनुपात यह बताता है कि एक औंस सोने से कितनी औंस चांदी खरीदी जा सकती है। यह अनुपात जितना अधिक होता है, सोने की तुलना में चांदी के दामों में उतनी ही कम मजबूती होती है। अब तक यह अनुपात करीब 90 के आस-पास चल रहा है, लेकिन संगठन इस अनुपात को 80 से नीचे रख रहा है जो इस बात का संकेत है कि चांदी में सोने से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।

वायरस से अनिश्चितता बरकरार

कुछ वाहन उपकरण निर्माताओं को जोखिम नहीं दिख रहा पर कुछ उत्पादन को लेकर हैं चिंतित

टी ई नरसिम्हन

कोरोनावायरस के संक्रमण के असर को लेकर देश के वाहन निर्माताओं की राय बंटी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे उनका उत्पादन प्रभावित होगा वहीं कुछ निर्माता कहते हैं कि उनके पास करीब एक महीने तक का माल है जिसे उन्होंने चीन में नववर्ष की छुट्टियों और नए ऑर्डरों की उम्मीद की वजह से अग्रिम तौर पर माल का भंडार रख लिया था। ये नए ऑर्डर सामान्य तौर पर छुट्टियों के बाद दिए जाते हैं। यह अवधि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक बनी रहती है।

विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक जिंस कीमतों में संभावित कमी और चीन के संकट की वजह से अपोलो टायर्स जैसी बैटरी और टायर कंपनियों के मार्जिन में मदद मिल सकती है। एमके की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के आपूर्तिकर्ता कुछ आपूर्ति से ही जुड़े हुए हैं और इसके लिए अन्य स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला की शुरुआत में देर हो सकता है और लघु अवधि में भारतीय मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) की लागत बढ़ सकती है।

हीरो मोटोकॉर्प ने कहा है कि कोरोनावायरस से भारत में कंपनी की निर्माण इकाइयों के लिए कुछ कलपुर्जों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसकी वजह से कंपनी ने उत्पादन की जो योजना बनाई थी उसके फरवरी महीने में करीब 10 प्रतिशत तक घटने की आशंका है। हालांकि इस महीने के दौरान डीलरों के लिए थोक बिक्री पर प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी ने कहा, 'चीन में बदल रहे हालात के मुताबिक ही उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।' हालांकि टीवीएस मोटर, होंडा और मारुति सुजूकी जैसी कंपनियों का कहना है कि अब तक उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि इन कंपनियों की चीन पर निर्भरता कम है। हालांकि इस बाबत इन कंपनियों ने कोई आंकड़ा मुहैया नहीं कराया है।

कार निर्माता कंपनियों मारुति और हुंडई का कहना है कि उत्पादन अब तक प्रभावित नहीं हुआ है लेकिन वे हालात पर नजर रख रही हैं। खबरों में कहा गया है कि हुंडई ने कलपुर्जों के अभाव की वजह से दक्षिण कोरिया के उलसान में अपने पांच प्रमुख एसेंबली संयंत्रों में कामकाज बंद कर दिया है। चीन की एमजी मोटर ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने बताया, 'कोरोनावायरस के प्रभाव को छोड़कर, मुझे फिलहाल बीएस-4 से बीएस-6 के बदलाव का कोई जोखिम नहीं दिख रहा है। हमारे पास दो कलपुर्जे चीन से आ रहे थे जिनमें अभी गतिरोध बना हुआ है। मेरा मानना है कि अगले एक हफ्ते या 10 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन स्थिति इससे आगे भी बदतर बनी रही तो हमारे लिए लगभग 3000 बीएस-4 वाहनों को लेकर चुनौती पैदा हो जाएगी, जिनके लिए दूसरे सभी अन्य कलपुर्जे हमारे पास हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक कलपुर्जे के लिए इंतजार करना होगा। इसके अलावा, हमें कोई जोखिम नहीं दिख रहा है। सभी उत्पाद बीएस-6 के लिए तैयार हैं।'

कोरोनावायरस संक्रमण से भारत में कंपनी की निर्माण इकाइयों के लिए कुछ कलपुर्जों की आपूर्ति प्रभावित हुई है

ऑटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की महानिदेशक विन्नी मेहता ने कहा कि मौजूदा हालात से ओईएम प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन यदि यह स्थिति अगले तीन सप्ताह या एक महीने तक बनी रही तो प्रभाव महसूस किया जाएगा। एसीएमए इंडिया ने 2019 में चीन से लगभग 4.2 अरब डॉलर के वाहन कलपुर्जों का आयात किया और समान अवधि में चीन को 41 करोड़ डॉलर का निर्यात किया।

हालांकि टाटा मोटर्स ने इस संबंध में भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया है, लेकिन एमके की रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पावधि में कोरोनावायरस के प्रकोप का चीन में टाटा मोटर्स (कुल राजस्व का 11 प्रतिशत) और मदरसन सूमी (6 प्रतिशत) की कमाई पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं वैश्विक स्तर पर जिंस कीमतों में संभावित गिरावट से बैटरी और टायर कंपनियों के मार्जिन को मदद मिल सकती है।

टीटीएमटी अपने कुल राजस्व का 11 फीसदी जेएलआर के निर्यात और चेरी जेवी के जरिये चीन से हासिल करती है। जेएलआर का चीन में संयुक्त उपक्रम संयंत्र चेंगशू में स्थित है जो कोरोनावायरस के केंद्र वुहान से दूर है। यदि अल्पावधि में कंपनी की चीन में बिक्री 25 प्रतिशत तक प्रभावित हुई तो कुल एबिटा आय वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में 5 प्रतिशत तक घट सकती है।

एमके की रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसन सूमी पर मामूली प्रभाव देखा जा सकता है क्योंकि कंपनी चीन क्षेत्र से अपने कुल राजस्व का सिर्फ लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा हासिल करती है। यदि अल्पावधि में चीन में उसकी बिक्री 25 प्रतिशत तक प्रभावित हुई तो कुल एबिटा आय में 3 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

'चीन जाने पर प्रतिबंध नहीं'

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि कोरोनावायरस के प्रकोप को देखते हुए चीन जाने या वहां से आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं जापान में एक पोत पर सवार आठ भारतीयों के कोरोनावायरस से संक्रमित होने के बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे जापानी अधिकारियों के संपर्क में हैं। एयर इंडिया ने गुरुवार को घोषणा कर दी कि कंपनी चीन की अपनी उड़ानों के निलंबन को 30 जून तक बढ़ा रही है। एयर इंडिया ने पिछले महीने दिल्ली-शांघाई की छह साप्ताहिक उड़ानों को 31 जनवरी से 14 फरवरी तक के लिए निलंबित कर दिया था।

विदेश में हालात

दक्षिण कोरिया के चौथे सबसे बड़े शहर की सड़कें गुरुवार को खाली नजर आईं और निवासियों ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। संक्रमण एक चर्च के जरिये फैला। दक्षिण कोरिया के देगु शहर के मेयर ने लोगों को घर के बाहर रखने की गुजारिश की है क्योंकि एक ऐतिहासिक चर्च में प्रार्थना करने गए 90 लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखे और दर्जनों नए मामले की पुष्टि हुई। चीन में इस वायरस के संक्रमण से अब तक 2,100 लोगों की मौत हो चुकी है। चर्च जाने वाली एक 61 वर्षीय महिला की संक्रमण जांच पॉजिटिव रही और ऐसी आशंका है कि उसी महिला से संक्रमण फैला। वहीं जापान में कोरोनावायरस से संक्रमण के कारण अलग रखे गए एक जहाज के दो बुजुर्ग यात्रियों की मौत हो गई। ईरान ने गुरुवार को कहा कि देश में तीन और लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।

एजेंसियां

सर्वेक्षण में बढ़ रही जटिलता

पृष्ठ-1 का शेष

सर्वेक्षण के इस दौर में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसने मामले को और जटिल बना दिया है। इसमें कुछ इस तरह के प्रश्न शामिल हैं जैसे, क्या आप कम से कम छह महीने से इसी जगह पर हैं? आप इससे पहले कहां रहते थे? क्या परिवार के सदस्यों की कहीं और जाने की योजना है? परिवार के सदस्य इससे पहले किस देश में रहते थे?

एनपीआर से जुड़े सवालों का जवाब न मिलने से नतीजों पर असर की आशंका

फिर कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिन्हें लोग शक की नजर से देखते हैं? उदाहरण के लिए धर्म से जुड़ा सवाल या क्या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है या 31 मार्च, 2014 के बाद खरीदे गए मकान के बारे में।

एनएसओ को उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक सहित कई राज्यों से शिकायत मिली है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल है जहां अभी कोई सर्वेक्षण नहीं हो रहा है।

पश्चिम बंगाल में एनएसओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, '78वें दौर का सर्वेक्षण कुछ स्थानों पर शुरू हुआ था लेकिन इसका विरोध बढ़ता गया और इस काम में लगे अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा हो गया। उन पर हमले हुआ और उनका घेराव किया गया। जिला प्रशासन का भी कहना है कि यह किसी भी सर्वेक्षण के लिए उचित समय नहीं है।'

पश्चिम बंगाल के फील्ड ऑफिस ने बुधवार की बैठक में इस बारे में तस्वीरें और अखबारों में आई खबरों को साझा किया। अधिकारी ने कहा, 'शुरुआत में हमने सोचा कि पलायन से जुड़े कुछ सवाल चिंता का विषय हैं। लेकिन लोग नाम और धर्म से जुड़े बुनियादी सवालों पर भी नाराज हो रहे हैं।'

पश्चिम बंगाल में कई अन्य सर्वेक्षण में रोक दिए गए हैं। इनमें सातवीं आर्थिक गणना, साविधिक श्रम बल सर्वेक्षण और असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण भी शामिल हैं। राज्य में केवल कृषि, उद्योग और बाजार मूल्य के आंकड़ों से जुड़े सर्वेक्षणों का काम ही चल रहा है।

बिहार में भी यही स्थिति है जहां सीमावर्ती इलाकों खासकर उत्तरी इलाके में एनएसओ के सर्वेक्षणों में समस्या हो रही है। बिहार में एनएसओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'लोग सर्वेक्षण के सवालों और सीएए में संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की रिहाइश और पलायन से संबंधित सवालों से स्थिति विकट हो रही है।'

मुख्य सांख्यिकीविद् प्रवीण श्रीवास्तव ने इस बारे में बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। आगे का रास्ता क्या है? पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रणव सेन ने कहा, 'अभी ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। सबकुछ राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका पर निर्भर करता है।' सेन आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि अगर बड़ी संख्या में लोग सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो इससे सर्वेक्षण के नतीजों पर फर्क पड़ेगा।

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को टालने का सुझाव देने का विशेषज्ञ समिति का फैसला ऐसे वक्त आया है जब सरकार 2020-21 और 2021-22 में उपभोक्ता व्यय पर लगातार दो सर्वेक्षण करने की योजना बना रही है। देश में रोजगार और बेरोजगारी की थाह लेने के लिए साविधिक श्रम बल सर्वेक्षण भी 2017-18 से नियमित रूप से हो रहा है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने पिछले साल नवंबर में खुलासा किया था कि 2011-12 से 2017-18 के बीच उपभोक्ता खर्च में चार दशक में पहली बार 3.7 फीसदी की गिरावट आई है जो गरीबी का स्तर बढ़ने का संकेत है। इसके बाद सरकार ने एनएसओ द्वारा 2017-18 में किए गए आधिकारिक सर्वेक्षण से पल्ला झाड़ने का फैसला किया था। इस रिपोर्ट को कार्यकारी दल ने जून, 2019 में मंजूरी दी थी लेकिन प्रतिकूल निष्कर्षों के कारण इसे रोक दिया गया।

सीएसएस जनवरी 2019 में कानून बना था। इसके तहत तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के खिलाफ देशभर में व्यापक प्रदर्शन हुए हैं।

ब्रांडों की पसंद में आलिया अव्वल

सोहिनी दास

अगर 60 से अधिक उम्र वाले ब्रांड को अगर अपने वादे में जोश भरने की जरूरत होगी तब उसे क्या करना चाहिए? या कोई नया कोला ब्रांड जब किसी वीडियो शेयर करने वाले मंच से जुड़ता है तब उसे क्या करने की जरूरत होती है या फिर किसी इलेक्ट्रिकल वस्तुओं के निर्माताओं को मिलेनियल से जुड़ना हो तब कैसी रणनीति होनी चाहिए? पिछले कुछ सालों में विभिन्न ब्रांडों ने अपने ग्राहकों को लक्षित करने के लिए मशहूर युवा अदाकारा आलिया भट्ट को चुना है।

सभी ब्रांड इसी चेहरे को पसंद करते हैं और इसके विज्ञापन करार में काफी तेजी देखी गई है। हाल के डेफ ऐंड फेल्प्स सेलिब्रिटी मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पडुकोणे के अलावा आलिया ही एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जो देश में विज्ञापन करार के लिए ज्यादा पैसे पाने वाले शीर्ष 10 सेलेब्रिटी की श्रेणी में शामिल है। उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेता को भी सातवें पायदान पर छोड़ दिया है और साथ ही विज्ञापन करार की होड़ में महेंद्र सिंह धोनी, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन और महिला अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान और अनुष्का शर्मा को छोड़ दिया है।

आलिया ने वर्ष 2018 और 2019 में बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी हैं और फिलहाल उन्होंने 4.5 करोड़ डॉलर तक का ब्रांड करार किया है। वह फैशन, फूड और बेवरिज तक के लिए विज्ञापन करती हैं और उन्होंने एक स्टार्टअप स्टाइल मंच स्टाइलक्रैकर में निवेश किया है। आखिर 26 साल की अभिनेत्री में ब्रांडों को कितनी उम्मीदें दिखती हैं?

एक ब्रांड इंटेलीजेंस और डेटा इनसाइट कंपनी टीआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन चंद्रमौलि के मुताबिक पुरुष प्रधान उद्योग में अपने बूते पर फिल्म को चला पाना उनकी बड़ी खूबी है। उनका कहना है कि उनकी शख्सियत में तार्किकता, भावनात्मक, महत्त्वाकांक्षी और संवाद करने में निपुणता ही उन्हें खास बनाती है। अगर महत्त्वकांक्षा के पैमाने पर भी देखा जाए तो वह अव्वल दिखती हैं। उन्होंने जिस तरह की फिल्में पसंद की हैं और जिस तरह एक ही ढर्रे वाली फिल्म के लिए इनकार किया है उससे यह अंदाजा मिलता है कि वह अपनी भूमिकाओं के साथ प्रयोग करने की इच्छुक हैं और उनकी फिल्में केवल बॉक्स ऑफिस की सफलता तक ही सीमित न रहे बल्कि विभिन्न तरह के दर्शक वर्ग को भाए। मार्केटिंग करने वालों का कहना है कि इसी वजह से ब्रांड आलिया को चुनते हैं।

आलिया हर साल एक ब्रांड के विज्ञापन करार के लिए करीब एक करोड़ रुपये लेती हैं और वह कई सेलिब्रिटी के मुकाबले ब्रांडों को किफायती लगती हैं। उनकी फीस की वजह से ही उनका दायरा बड़ा है और मार्केटिंग से जुड़े लोगों का कहना है कि आलिया सबके बजट में फिट होने के साथ ही विभिन्न उम्र वर्ग और हर जगह अपील रखती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी दमदार मौजूदगी से ब्रांडों को भी ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिलता है।

हरीश बिजूर कंसल्ट्स के संस्थापक और सीईओ हरीश बिजूर का मानना है कि आलिया के पास खाली स्लॉट हैं जिसे भरा जा सकता है क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट हैं जिनकी वजह से उनके पास वक्त नहीं होता। आलिया की खास बात यह भी है कि उनकी अपील बिल्कुल अलग तरह के ब्रांडों के बीच भी है। वह नए दौर का एक मुफीद चेहरा हैं जिनका इस्तेमाल हर तरह के ब्रांड अपने प्रचार के लिए कर सकते हैं। वह कहते हैं, 'उनके ताजातरीन चेहरे वाली शख्सियत को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह पड़ोस की कोई लड़की हैं। वह युवा होने के साथ ही आधुनिक भी लगती हैं और वह हरफौनमौला हैं।'

ब्रांडों का कहना है कि उनको लेकर हर जगह चर्चा जरूर होती हैं चाहे वह उनके द्वारा चुनी गई फिल्में हों या फिर वह जिस तरह अपनी निजी जिंदगी में रहती हैं उसको लेकर भी सुर्खियां बनी रहती हैं। वह अत्याधुनिक पीढ़ी के उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ जाती हैं। विक्को के निदेशक संजीव पेंढारकार ने अपने एक नए विज्ञापन अभियान के लॉन्च के मौके पर कहा, 'विको वज्रदंती 1952 से ही घर-घर में जाना-पहचाना नाम बन चुका है। इससे वफादार उपभोक्ताओं का एक बड़ा आधार जुड़ा है। युवा पीढ़ी और मिलेनियल में अपील बनाने की मार्केटिंग रणनीति में आलिया से बेहतर चुनाव क्या हो सकता है।'

विको की तरह के कई ब्रांड उनकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी का फायदा उठाने में दिलचस्पी रखते हैं। आलिया के इंस्टाग्राम पर 4.3 करोड़ फॉलोअर हैं जबकि यूट्यूब पर 13 लाख सबस्क्राइबर और ट्विटर पर 2 करोड़ फॉलोअर हैं। वह अपने टाइलमलाइन पर ब्रांड का प्रचार करते हुए उनकी कहानी भी साझा करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि उनका सोशल मीडिया मंच कुछ पेशेवर प्रबंधन के साथ और बेहतर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तब आलिया की ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाएगी और उनके ब्रांड करार में और इजाफा हो सकता है।

ब्रांड करार की फेहरिस्त

मेकमाइट्रिप	(पर्यटन)
नोकिया	(स्मार्टफोन)
फोनपे	(फिनटेक)
कैप्रेसी, वीआईपी इं.	(हैंडबैग)
फ्लिपकार्ट	(फैशन, ई कॉमर्स)
मेबलिन	(सौंदर्य)
गार्नियर	(हेयर केयर)
विको वज्रदंती	(टूथपेस्ट)
सनफीस्ट डार्क फैंटसी	(बिस्कुट)
पेप्सी लेज	(स्नैक्स)
कोका कोला	(बेवरिज)
कैडबरी पर्क	(चॉकलेट)
फिलिप्स	(हेयर ड्रायर)
स्टैंडर्ड हैवेल्स	(पंखे)